Every leader of a political party, whichever might be one's affiliation, or every worker of a political party whatever the party might be, is responsible for seeing that such things do not happen in his region, in his area, in his surroundings, in his State, in his country. So, I again request you to keep the matter as it is. You can bring whatever issues you like to bring at the time when we discuss this matter.

Now, I start the Short Duration Discussion. Shrimati Sarala Maheshwari to speak.

SHORT DURATION DISCUSSION

Serious situation in Assam in view of recent ethnic clashes and massacre of refugees in Barpetta district.

श्रीमती सरला माहेश्वरी (पश्चिमी बंगाल) : माननीया उपसभापति महोदया, आज बारपेटा की खास घटना के संदर्भ में असम की गंभीर समस्या पर चर्चा करने के लिए मैं खड़ी हुई हूं। उपसभापति महोदया, बारपेटा तथा असम में ब्रह्मपुत्र के उत्तरी किनारे पर बसा हुआ क्षेत्र पिछले कई वर्षों से जनसंहारों की आग में जलता रहा है। ये तमाम घटनाएं, जनसंहार की ये तमाम त्रासदियां अपने आप में कोई अलग-थलग घटनाएं नहीं हैं। इन तमाम घटनाओं का बहुत गहरा संबंध इस पूरे क्षेत्र के जातीय स्वरूप तथा सामाजिक, आर्थिक विकास के साथ जुड़ा हुआ है। उपसभापति महोदया, जहां तक इस बारपेटा के निर्मम नृशंस नरसंहार का सवाल है, इस घटना की जितनी निंदा की जाए शायद शब्द कम पड़ेंगे उपसभापति महोदया, असम जातीय संघर्ष की आग में पिछले डेढ़ दशक से जल रहा है। पिछले वर्ष ही कोकराझार में भयानक नरसंहार हुआ था जिसकी याद आज भी हमारे दिलो-दिमाग में ताजा है। लेकिन फिर भी इस विशेष बारपेटा की घटना के संदर्भ में जो नई बात हुई है वह यह है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि जब किसी सरकारी शरणार्थ शिविर में उग्रवादियों ने इस तरह का बर्बर हमला किया हो और इस बर्बर हमले में मासूम बच्चों सहित 75 लोगों की जानें चली गईं, सैंकड़ों लोग घायल हो गए। महोदया, यह घटना इस बात का प्रमाण है कि असम की राज्य सरकार इस तमाम क्षेत्र में जो वारदातें होती रही हैं या हो रही हैं उनके प्रति कितनी संवेदनशून्य हो चुकी है। खास कर पिछले दो महीनों से यह पूरा क्षेत्र जल रहा है। पिछली 28 मई को ही काकराझार जिले में एक ही संप्रदाय के दो सौ घरों को फूंक दिया गया जिसमें 25 लोग मारे गए थे। उस समय भी हजारों लोग अपने घरबार से उजड़कर शरणार्थी शिविरों में रहने को मजबूर हुए थे। पिछले एक हफ्ते से तो पूरा बारपेटा शहर जल रहा था। 19 जुलाई से वारदातें होनी शुरू हो गई थीं और 21 जुलाई को वहां अनिश्चितकाल के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया, देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिए गए। यानी स्थिति की गंभीरता के सारे के सारे संकेत मौजूद थे 20 जुलाई को बारपेटा के 15 गांवों को फूंक दिया गया जिसके कारण बाध्य होकर हजारों लोग बारपेटा रोड शहर के शरणार्थी शिविर में आने को मजबूर हुए। सिर्फ इतना ही नहीं 23 जुलाई के इस कांड के पहले ही मंत्री महोदय जानते होंगे कि इस बात के तमाम सबूत मिल चुके थे, तमाम संकेत मिल चुके थे कि शरणार्थी शिविरों पर हमला हो सकता है। बारपेटा रोड पर बनाए गए इस शरणार्थी शिविर का दौरा करने के बाद हमारी पार्टी की असम राज्य इकाई ने सरकार को यह कहा

था कि यह जो सरकारी शरणार्थी शिविर हैं ये सुरक्षित नहीं हैं, इनकी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की जानी चाहिए लेकिन इन तमाम प्रमाणों तमाम सबूतों, तमाम संकेतों के मिलने के बावजूद सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं की गई और यह निर्मम हादसा हो जाने दिया गया। महोदया, 28 मई को काकराझार की घटना जिसके बारे में मैंने कहा है, एक ही संप्रदाय के दो सौ घरों को फूंक दिया गया था, 25 लोगों को जिंदा जला दिया गया था। उस घटना पर टिप्पणी करते हुए वहां के मुख्यमंत्री की क्या प्रतिक्रिया थी? वहां के मुख्यमंत्री ने कहा—"यह घटना गैर-आदिवासियों द्वारा आदिवासियों की जमीन को लूटने का एक पुराना मामला है और उसी की प्रतिक्रिया में यह घटना हुई"।

महोदया, कहने का मतलब यह है कि यह जो जातीय दंगे हो रहे हैं, इन जातीय दंगों के प्रति असम की सरकार का रवैया कितना उदासीन, कितना संवेदनशून्य है। मैं यह कहना चाहूंगी कि पिछले डेढ़ वर्षों में इन जन-संहारों के बावजूद अभी तक सरकार की ओर से किसी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई। आज स्थिति यह है कि 50,000 से ज्यादा लोग अपने घर-बार छोड़ कर खौफ और आतंक के वातावरण में जीने को मजबूर हैं। आज उस पूरे क्षेत्र की स्थिति यह है, मुझे यह कहना है, कि वहां लोग नहीं रह रहे, वहां स्थिति यह है—"खेमा डाले खौफ खड़ा है, चारों जानिब से उजड़ते शहर में"। आज यह स्थिति बना दी है आपने, कि सिर्फ वहां खौफ जिंदा है, आतंक जिंदा है, लोग जिंदा नहीं हैं। इस स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है, आपकी केन्द्रीय सरकार या असम की राज्य सरकार?

महोदया, मैं यह कहना चाहूंगी कि यह एक गंभीर समस्या है, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। क्या हम इस क्षेत्र को नहीं जानते? यह भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र, यह सीमायी प्रदेश, वास्तव में जनजातियों का क्षेत्र है। असम सहित इस पूरे क्षेत्र की आबादी का बीस प्रतिशत हिस्सा जनजातियों का है। चीन के दक्षिणी इलाकों, दक्षिण एशिया तथा आसपास के तमाम क्षेत्रों से प्रागैतिहासिक काल से लेकर इन जनजातियों का आवागमन होता रहा है और यह आवागमन अठाहरवीं सदी तक जारी रहा। आज हम जिस बोडो क्षेत्र की बात कर रहे है, इस क्षेत्र में बोडो जाति आकर बसने वाली सबसे पुरानी जाति है। यह संख्या की दृष्टि से भी सबसे ज्यादा है। महाभारत और पुराणों में भी जिस जाति की चर्चा की जाती है किरात के रूप में, वह यही जाति है। हमारे प्राचीन साहित्य और लोकगाथाओं को देखने से पता चलता है कि किरातों ने हमारी भाषा और संस्कृति को किस तरह प्रभावित किया है।

महोदया, इतिहास के इस वर्तमान मुकाम पर यह तमाम जनजातियां एक भयावह संक्रमण के दौर से गुजर रही हैं। हजारों वर्षों की अपनी निद्रा से जागकर आज वह भारत वर्ष में अपनी अस्मिता की तलाश कर रही है। हमारे संविधान के ढांचे में उनको सामाजिक न्याय मिल सके, उनकी अस्मिता की रक्षा हो सके, उनकी भाषा और संस्कृति की रक्षा हो सके, इसके लिए यह संघर्ष कर रही है। खासतौर पर आजादी के बाद इन तमाम दशकों में संचार व्यवस्था के विकास तथा आधुनिक शिक्षा के जरिए इन जनजातियों का एक ओर जहां अलग-थलगपन हुआ है, वहीं इन जातियों के बीच राष्ट्रीय प्रगति की चेतना भी विकसित हुई है। पूंजीवादी विकास की धारा ने एक तरफ जहां इनका अलगाव दूर किया है, जहां इनको जोड़ा है वहीं इसी पूंजीवादी व्यवस्था ने इनको अंदर से तोड़ा भी है। इनके बीच पैदा हुई नई चेतना अपनी अभिव्यक्ति के नए रास्तों को तलाश रही है और यही कारण है कि आज जहां संभव हो रहा है वह जनसंख्या की दृष्टि से भौगोलिक दृष्टि से क्षेत्रीय स्वायतता की मांग कर रहे हैं।

महोदया, मैं यह कहना चाहूंगी कि हमारे पूंजीवादी, सामंती शासकों का

[श्रीमती सरला माहेश्वरी]

रवैया इन जनजातियों के प्रति कभी भी सहानुभूति का नहीं रहा क्योंकि यह जनजाति के लोग ही वह गरीब, शोषित, पीड़ित लोग थे, जो जंगलों में, खदानों में, वनों में सबसे सस्ते श्रम के स्रोत हुआ करते थे। इन जनजातियों के लोगों को दोहरे शोषण का सामना करना पड़ता था, एक तरफ वर्गीय शोषण का और दूसरी तरफ जातीय भेदभाव का। इसीलिए इस लंबे अरसे से चले आ रहे शोषण के विरुद्ध इनमें तीव्र आक्रोश की भावनाएं जन्म लेने लगीं।

महोदया, इतिहास के पन्नों को कुछ पलटा जाए तो हम देखेंगे कि हमारे देश में ब्रिटिश शासकों ने ईसाई मिशनरियों के जरिए इन जनजातियों को देश की बाकी जनता से काटकर रखने की नीति बनाई थी। अंग्रेजों ने ही वन संपदा पर इन जनजातियों के प्राकृतिक अधिकार को छीन लिया था और उन्हें अपनी जमीनों से बेदखल कर दिया। आर्थिक तौर पर तबाह कर दिए गए जनजातियों के इन्हीं लोगों को ब्रिटिश काल में सब जगह सबसे कम मजदूरी पर खदानों में और बागानों में काम करने दिया गया।

आजादी के बाद कांग्रेस सरकार का रवैया हालांकि कुछ मानवीय जरूर रहा। भारतीय संविधान की पांचवीं और छठी अनुसूची के संघीय ढांचे के अंतर्गत आदिवासियों को अपनी पहचान को सुरक्षित रखने तथा जनतांत्रिक तरीके से उन्हें आबादी के अन्य हिस्सों के साथ जोड़ने की कोशिश की गई। डा. वेरियम ऐल्विन की तरह आदिवासियों के सच्चे हमदर्द को लेकर पंडित नेहरू की सरकार ने आदिवासियों के उत्थान की जो योजना घोषित की, उसका सार यह था कि जनजातियों को अपनी खुद की प्रतिभा के साथ विकसित होने का अवसर दिया जाना चाहिए। उनकी संस्कृति और उनके जीवन के परंपरागत रूपों की रक्षा की जानी चाहिए। जमीन और जंगलातों पर उनके पारंपरिक अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए। आदिवासी इलाकों में प्रशासनिक और विकासमूलक कार्यों के लिए आदिवासी समाज के कार्यकर्ताओं को तैयार किया जाना चाहिए उन पर जटिल नौकरशाही का बोझ नहीं डाला जाना चाहिए।

उपसभापति महोदया, डा. ऐल्विन और पंडित नेहरू के जो सपने थे और आदिवासियों के प्रति डा. ऐल्विन की जो धारणा थी कि आदिवासियों का न्याय बोध, उनका व्यक्तिगत शौर्य और उनका जो स्वर्ग था, उस स्वर्ग को तोड़ा न जाए। यह डा. ऐल्विन की अटूट धारणा थी लेकिन न तो डा. ऐल्विन और न ही पंडित नेहरू के सपने साकार हो सके। पूंजीवादी निर्मम व्यवस्था ने उन तमाम कल्पनाओं पर आधारित सपनों को चकनाचूर कर दिया और एक ठोस वास्तविकता, जो निर्मम ठोस वास्तविकता थी, उनसे उनका सामना पड़ा।

महोदया, मैं यह कहना चाहूंगी कि आज आदिवासियों के बीच जो अशांति हम देख रहे हैं, जो बेचनी हम देख रहे हैं, यह सब उसी का परिणाम है। मैं यह कहना चाहूंगी कि बारपेटा की इस घटना के सिलसिले में इतिहास के इन चंद पृष्ठों का जिक्र करना मैंने इसलिए जरूरी समझा क्योंकि मैं समझती हूं कि इतिहास के उस दौर को समझे बिना हम शायद भविष्य को संवार नहीं दे पाएंगे।

महोदया, असम में एक लंबी लड़ाई के बाद आदिवासियों के लिए स्वायत्त परिषद की मांग को स्वीकार किया गया। शुरू में जब ट्राईबल काउंसिल ऑफ असम ने स्वायत्तता की मांग को उठाया था तब कांग्रेस सरकार ने इसे विखराव की मांग कहकर ठुकरा दिया था। बोड़ो भाषा को मान्यता देने की मांग भी स्वीकार नहीं की गई। लंबे आंदोलन के बाद इस मांग को स्वीकार गया है। असम में जनता पार्टी की पहली सरकार काल में पी.टी.सी.ए. के एक नेता को मंत्री भी बनाया जैसा कि हम देखते हैं संसदीय राजनीति

में आम तौर पर जो होता है, आदिवासियों का वह नेतृत्व भी अन्य बुर्जुआ पार्टियों की तरह भ्रष्ट हो गया और आदिवासियों के इसी भ्रष्ट नेतृत्व के कारण "आबसू" का जन्म हुआ, आल बोड़ो स्टूडेंट्स यूनियन का जन्म हुआ जिसने ब्रह्मपुत्र के उत्तरी किनारे पर एक अलग राज्य के लिए आंदोलन शुरू किया। उन दिनों इस क्षेत्र में यही नारा गूंज रहा था—"बोड़ो लैंड नहीं तो शांति नहीं"।

असम की सरकार ने इस आंदोलन के विरुद्ध चरम दमनकारी रवैया अख्तियार किया क्योंकि असम गण परिषद की जो विचारधारा थी वह अन्धराष्ट्रवादी विचारधारा थी। वे जबरदस्ती असमिया राष्ट्रीयता के अंदर ही आदिवासियों के विलय की मांग को मान्यता दे रहे थे। इसलिए मैं यह कहना चाहूंगी कि असम के आदिवासियों और गैर-आदिवासियों के बीच अविश्वास की जो खाई हमारे शासक वर्गों ने चौड़ी की, उस खाई के चलते परिणाम यह हुआ कि स्थिति लगातार बिगड़ती गई। हालांकि इस बिगड़ती हुई स्थिति को देखते हुए बहुत बड़े जातीय दंगों को सिर्फ इस कारण रोका जा सका क्योंकि वहां की तमाम राजनीतिक पार्टियों ने यह विश्वास दिलाने की कोशिश की कि आदिवासी क्षेत्रों को स्वायत्तता प्रदान की जाएगी और आदिवासियों की मांग को माना जाएगा। इसीलिए बहुत बड़े जातीय दंगे उस समय भड़क नहीं सके।

महोदया, इसके बाद वी.पी. सिंह की सरकार ने आदिवासी क्षेत्रों की स्वायत्तता का अध्ययन करने का आश्वासन दिया। चंद्रशेखर सरकार के काल में इसके बारे में तथ्यों को बटोरने के लिए एक दल को भेजा गया। इस पूरी प्रक्रिया में असम के सभी आदिवासी समूहों के बीच अपने अधिकारों की चेतना बढ़ने लगी। इसमें कोई संदेह नहीं कि आदिवासी समुदाय के लोगों के लिए समानता और समान अधिकार, राष्ट्रीय और जातीय भेदभाव की समाप्ति, स्वायत्तता, भूमि-सुधार और आरक्षण के आधार पर आर्थिक विकास की मांगें आदिवासियों के आंदोलनों की बिल्कुल सही और जनतांत्रिक मांगें हैं। हमें इन मांगों का तहेदिल से स्वागत करना चाहिए, क्योंकि तभी यह आदिवासी आंदोलन वास्तविक रूप से मुख्य जनतांत्रिक धारा से जुड़ पाएंगे। लेकिन इसके साथ ही यह भी सच है कि इन आदिवासी आंदोलनों में कुछ ऐसे जनतंत्र विरोधी तत्व उभर आए हैं। जिनका पुनरुत्थानवादी रुझान है। यह तमाम रुझान आदिवासी आंदोलन को जनतांत्रिक धारा से काटकर रखने की भूमिका ही अदा कर रहा है। महोदया, मुझे कहना पड़ता है कि हमारा शासक वर्ग चा वह असम की सरकार हो, चाहे वह दिल्ली की सरकार हो आदिवासी आंदोलन को विभाजित करने की हर संभव कोशिश कर रही है। माननीय आंतरिक सुरक्षा राज्य मंत्री जी बैठे हुए हैं। उन्होंने खुद अपनी भेंटवार्ता के दौरान इस बात को स्वीकार किया है कि राजनीतिक उद्देश्यों की खातिर, राजनीतिक निहित स्वार्थों की खातिर राजनेताओं ने इस तरह की चीजों को प्रोत्साहित किया है और इसी कारण यह जो बीज उन्होंने बोए थे, उस बीज की अनिवार्य फसल के रूप में आज आसाम की इस समस्या को हम देख रहे हैं। वह आसाम जो कि बहुभाषी, बहुसांस्कृतिक राज्य है जिस राज्य के लोग कभी मिलकर रहा करते थे, आज वह आसाम जातीय विद्वेष की आग में जल रहा है, जातीय दंगों की आग में जल रहा है। इसके लिए जिम्मेदार हमारी सरकार खास कर कांग्रेस सरकार, असम की वहां की कांग्रेस सरकार का यह रवैया रहा है और लगातार पिछले कई दशकों से यह रवैया चलता रहा अपने निहित स्वार्थों की खातिर। आदिवासियों की उभरती हुई नई चेतना के जो संगठन खड़े हो रहे थे, उन आदिवासियों के संगठनों को अपने निहित स्वार्थों के लिए अलग-अलग गुटों में बांटा गया और इन गुटों के चलते वहां जो विभिन्न सम्प्रदाय के लोग थे, उन विभिन्न सम्प्रदायों के बीच में एक दीवार खड़ी करने की कोशिश की गई।

[श्रीमती सरला माहेश्वरी]

उपसभापति महोदया, इतिहास गवाह है कि शासक वर्ग की इस राजनीति में आज असम में एक नारा चल रहा है– "एक और त्रिपुरा नहीं होने देंगे।" किस तरह त्रिपुरा में कांग्रेस ने टी–एन. बी., टी.यू.जे.एस. का इस्तेमाल किया। वर्षों के प्रयास से वामपंथी दलों ने वहां पर जातीय एकता की जो एक भूमि तैयार की थी, उसको तोड़ने की कोशिश की। खुद हमारे पश्चिमी बंगाल में ऐसा किया, लेकिन सफल नहीं हुए। परन्तु यह साजिशें चलती रही अपने सुद्ध निहित स्वार्थों की खातिर! महोदय मैं यह कहना चाहूंगी कि आज यह जो बोडो सिक्योरिटी फोस का दबदबा वहां चल रहा है और इस संगठन के जरिए जिस उग्र वादी, पुनरुत्थानवादी रुझान को बल दियाजा रहा है, उसके पीछे अगर कोई जिम्मेदार है तो आसाम की सैकिया सरकार जिम्मेदारहै। जिस तरह वहां केमु ख्य मंत्री और केन्द्र में बैठे हुए हमारे गृह मंत्री भी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि मुख्य मंत्री एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप के विरुद्ध भड़का रहे हैं। सत्ता की बंदर बांट कर रहे हैं। हो क्या रहा है इसके चलते? वह जो वहां का मौडरेट ग्रुप है, जो चाहता है कि भारतीय संविधान के अंदर रहते हुए हम अपनी स्वायत्तता के अधिकार को हासिल करें। आज हो क्या रहा है कि इन्होंने अपने निहित स्वार्थों के चलते उस मौडरेट ग्रुप को अलग-थलग कर दिया है। उस मौडरेट ग्रुप के प्रति जनता के बीच में विश्वास नहीं रहा और खुद केन्द्र के गृह मंत्रियों में, कहा तो यही जा रहा है कि उनके बीच में समन्वय नहीं है। अब असलियत क्या है यह तो मंत्री जी बताएंगे। लेकिन हकीकत यह है कि कहीं भी समन्वय नहीं है। न तो केन्द्रीय गृह मंत्रियों में समन्वय है और असम के जो मुख्य मंत्री हैं और वहां की जो सत्तारूढ़ सरकार है, उस सत्तारूढ़ सरकार की तरफ से भिन्न-भिन्न गुटों को समर्थन दिया जा रहा है। इसीलिए आज वहां हालत काबू से बाहर होती जा रही है। उप-सभापति महोदया, मैं यह बताना चाहूंगी कि यह जो बरपेटा की नृशंस और निर्मम घटना घटी, वहां के हमारे सांसद लगातार इस बात की कोशिश कर रहे हैं बार-बार टेलीफोन से सम्पर्क कर रहे हैं, दौड़-दौड़कर सम्पर्क कर रहे हैं, सरकार से सम्पर्क कर रहे हैं, असम की सरकार से सम्पर्क कर रहे हैं, परन्तु कोई मिलने वाला नहीं है। यहां दिल्ली में सम्पर्क कर रहे हैं। बताया गया कि एक गृह मंत्री बीमार हैं और दूसरे मीटिंग में हैं। कोई सम्पर्क नहीं किया गया। घटना 18 तारीख से घटनी शुरू हुई और कोई सिक्योरिटी फोर्स नहीं भेजी गई। आश्चर्य की बात है कि यह सब जानते हुए भी न तो केन्द्र सरकार ने कुछ किया और न राज्य सरकार ने ही कुछ किया। हमारे मंत्री जी वहां की हालत बताएंगे कि वहां तो 22 तारीख को ही मंत्रीगण पहुंचे थे और मुख्य मंत्री भी पहुंचे थे। लेकिन हमें जो खबर है कि वहां पर मंत्रियों का दल जाकर जनता की समस्याओं का समाधान नहीं कर रहा था, वहां सिक्योरिटी फोर्स भेजने की बात नहीं कर रहा था। वहां मंत्री आपस में लड़ रहे थे, झगड़ा कर रहे थे और वहां की जनता का यह कहना था कि मंत्रियों ने आ कर हमारी स्थिति को और बदतर बना दिया है। अब किस पर भरोसा करें? एक शहर जल रहा है, एक पूरा क्षेत्र जल रहा है और आपके मंत्री वहां लड़ रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। समझ में नहीं आता कि इस तरह की राजनीतिक समझदारी के अभाव में आप असम जैसे प्रदेश में कैसे शांति बनाए रख सकेंगे? भारत की एकता और अखण्डता की रक्षा कर सकेंगे? हम जानते हैं कि असम एक ऐसा क्षेत्र है जहां साम्रयाज्य-वादी ऐजेंसियां लगातार कोशिशें कर रही हैं कि उस को तोड़ा जाए। वहां जो जातीय विभिन्नताएं हैं उन जातीय विभिन्नताओं के आधार पर उन्हें तोड़ने की कोशिशें की जा रही हैं। हमारे बहुत से लोग आज इस बात को उठा रहे हैं, वे भी यही बात कर रहे हैं कि बंगलादेशियों को अनुप्रदेश न दिया जाए। महोदया, मैं इस बात से इंकार नहीं करती कि बंगलादेशियों का अनु प्रवेश हो सकता है लेकिन अगर ह

इस बात को कहें कि वहां बोडो क्षेत्र में सारे के सारे लोग बंगलादेशी हैं और आज हो क्या रहा है कि बंगलादेशी विदेशियों का नाम ले कर सारा का सारा आंदोलन मुसलमानों के विरुद्ध चलाया जा रहा है। बंगलादेशी मतलब मुसलमान। हो क्या रहा है इसके चलते महोदया कि वे लोग, वे सम्प्रदाय जो आपस में शांति के साथ रह रहे थे लेकिन आज बोडो लोगों के बीच में और गैर-बोडो लोगों के बीच में विभाजन खड़ा कर रहे हैं अपने स्वार्थों के चलते और इसके चलते आज जब कि इस जनसंहार की घटना में बोडो लोग भी प्रभावित हुए हैं, गैर-बोडो लोग भी प्रभावित हुए हैं। लेकिन आपने क्या किया? आपकी सरकार ने क्या किया? आपकी सरकार ने उन लोगों को विश्वास में नहीं लिया। हमने तो यह चाहा था और हमेशा यह मांग की थी कि बोडो स्वायत्त परिषद की स्थापना हो। तमाम पार्टियों को आप विश्वास में लीजिए और बोडो व गैर बोडो सम्प्रदायों के लोगों को विश्वास में ले कर बैठिए और बातचीत करिए। गांवों को आधार बनाइए, कंटीग्यूअस जो एरिया है उस को लेकर आधार बना कर आप काम करिए लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। असम असेंबली में बोडो विधेयक पारित कर दिया गया और इतना सारा कनफ्यूज़न वहां पर पैदा कर दिया गया, इतने सारे विवाद वहां पर पैदा कर दिए गए। यह काम करने का सही तरीका नहीं है। जहां पहले से ही इतने विवाद मौजूद हों, इतने आपस में मतभेद पैदा हों, आपस में एक-दूसरे के प्रति अविश्वास की भावना हो, वहां पर अगर आप इस तरह काम करेंगे और मुझे अफसोस है कि हमारे यहां कुछ पार्टियां, कुछ साम्प्रदायिक पार्टियां और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि सत्तारूढ़ पार्टी, कांग्रेस पार्टी का भी एक बड़ा तबका लगातार बंगलादेश प्रवेशियों की बात पर ही ज़ोर दे रहा है जब कि असम की जो जनगणना है वह यह बताती है कि पूरे भारतवर्ष में जनसंख्या जिस प्रतिशत से बढ़ी है, उस प्रतिशत से असम में नहीं बढ़ी

बल्कि एक प्रतिशत कम है। इन तमाम तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए अगर हम एक गलत प्रचार अभियान चलाएंगे तो उसके बहुत भयावह परिणाम होंगे और इसके चलते हम कभी भी इस समस्या को सुलझा नहीं पाएंगे। उपसभापति महोदया, मैं इसलिए कहना चाहूंगी कि आज जरूरत इस बात की है कि इस समस्या की गंभीरता को समझते हुए और बरपेटा में जो यह निर्मम, नृशंस हत्याकांड हुआ है जिसके पीछे यह साफ कहा जा रहा है कि वहां के मुख्यमंत्री का ढुलमुल रवैया वहां के मुख्यमंत्री की अवसरवादिता है और जो नीति ब्रिटिश साम्राज्यवादी चला रहे थे, फूट डालो और राज करो की नीति, वही नीति आज वहां के मुख्यमंत्री अपना रहे हैं और इस फूट डालो, राज करो की नीति के चलते आज हालत इतनी बदतर होती जा रही है। मैं यह कहना चाहूंगी उपसभापति महोदया कि हमारे लिए यह बहुत ही चिंता की बात है, बहुत ही सोच की बात है कि आज अगर इस तरह की नीतियां जारी रहती हैं, इस तरह की फूट डालो, राज करो की नीतियां जारी रहती हैं और आदिवासी लोगों को विश्वास में नहीं लिया जाता तो समस्या हमेशा बिगड़ती ही रहेगी। हुआ क्या था इस बरपेटा की खास घटना के संदर्भ में?

उपसभापति महोदया, मैं यह कहना चाहूंगी कि यह बरपेटा की घटना, जो इतना निर्मम हत्याकांड हुआ, सिर्फ बोडो लोग नहीं मारे गए, गैर-बोडो लोग भी मारे गए लेकिन इसके बावजूद सारा का सारा प्रचार इस तरह चलाया गया। महोदया, घटना की शुरूआत 13 तारीख को हुई थी। मंत्री जी जानते होंगे जब वहां एक बम विस्फोट हुआ और पुलिस के छह लोग मारे गए और उसके बाद में सादी पोशाक में पुलिस वहां गई और आम बोडो लोगों को जिनका कोई मतलब नहीं था, उन को पकड़ा गया। इसका परिणाम यह हुआ कि बोडो लोग मुसलमानों के विरुद्ध और मुसलमान बोडो के विरुद्ध हो गए और उन का आपस

[श्रीमती सरला माहेश्वरी]

में फसाद शुरू हो गया। वहां कई तरह की घटनाएं घटीं। लेकिन सरकार की ओर से कोई कार्यवाही नहीं की गई।...

उपसभापति महोदया, मैं जिस बात को जोर देकर कहना चाहती हूं वह यह है कि बरपेटा की घटना कोई अलग घटना नहीं है। अगर आप चाहते है कि वास्तव में बोडोलैंड की समस्या का समाधान हो, हमारे मंत्री महोदय ने एक प्रयास किया, हम भी उनकी पीठ थपथपा देते, लेकिन इस बरपेटा की घटना ने यह प्रमाणित कर दिया है कि आप सिर्फ बातें करते हैं। असम के मुख्य मंत्री भी सिर्फ बातें करते रहे। बोडो स्वायत्त परिषद की बात करते रहे लेकिन स्वायत्ता के नाम पर कहीं भी कोई चीज नहीं थी। अगर वास्तव में बोडो लोगों को विश्वास में लिया गया होता, उन के लिए वास्तव में पैकेज रखा गया होता तो वास्तव में बात समझ में आती। लेकिन आपने उन को तोड़ने का काम किया। एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप से तोड़ने का काम किया और इसके चलते बोडो सैक्युरिटी फोर्स की तरह का एक उग्रवादी संगठन, एक पुनरुथानवादी संगठन इतना शक्तिशाली हो गया।

उपसभापति महोदया, मैं बताना चाहती हूं कि बरपेटा के नृशंस हत्याकांड के लिए केन्द्रीय सरकार भी उतनी ही दोषी है जितनी कि राज्य सरकार दोषी है। तमाम तथ्य को जानते हुए, तमाम संकेतों के मिलने के बावजूद न तो राज्य सरकार ने काम किया और न केन्द्रीय सरकार ने कोई काम किया। इसलिए मैं मांग करती हूं कि असम के मुख्य मंत्री को इतनी बड़ी निर्मम हत्याओं के बाद सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं जानना चाहूंगी गृह मंत्री से कि आप क्या कर रहे थे जब मासूम बच्चे वहां मारे जा रहे थे। वहां पर नृशंस हत्याकांड चल रहा था। आपने रोकने की कोशिश की? ऐसा नहीं हुआ। इसीलिए यह निर्मम हत्याकांड हुआ। मैं मांग करती हूं कि तमाम मासूस लोग, करीब 60 हजार लोग जो अपने घरों से बेदखल हो कर मारे मारे फिर रहे हैं, जो अपने घरों से उजड़े हुए लोग हैं, उन की सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। उन के पुनर्वासन की व्यवस्था की जाए। इस जघन्य हत्याकांड में जो लोग प्रभावित हुए हैं उन को पूरी सुरक्षा दी जाए। (**समय की घंटी**)

इस के साथ ही मैं पूरे सदन से और आप से अपील करना चाहती हूं कि इस खूनखराबे और हत्याकांड को बंद तभी किया जा सकता है जब आप निहित स्वार्थों के लिए जनता के बीच में फूट डालने और अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने का काम बंद करेंगे। यह हमारे देश की एकता और अखंडता के लिए जरूरी है कि सारा असम जो कि बहुराष्ट्रीय और बहु-संस्कृति वाला प्रदेश है, उसे एक रखा जाए। अगर उसे एक नहीं रख पाए तो यह भारत के लिए खतरनाक सिद्ध होगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप अपनी सहृदयता का परिचय दें। फटे हुए दिलों को सीया जा सकता है। अगर हमारे मुख्य मंत्री के पास उजली नजर की सुई हो तो फटे हुए दिलों को सीया जा सकता है बद इरादों से काम करेंगे तो कुछ नहीं होगा और इसी तरह के हादसे दोहराए जाएंगे और असम इसी तरह से जलता रहेगा।

धन्यवाद।

SHRI BHUBANESWAR KALITA (Assam): Madam Deputy Chairman, I rise to express my deep sorrow over the incident and to offer condolences to the families of those who had died in the massacre which has put all of us to shame. The massacre which has happened after the Nellie incident is really a more shocking one because the people were killed in the refugee camps. It is really a matter of concern for all of us. Madam, the issue which has been raised

is a very serious issue. It concerns not only the Bodos and non-Bodos but it attracts the attention of the whole nation. The Bodo Accord was signed on February 20, 1993 after a long-drawn-out agitation by the Bodo people on the north bank of the Brahmaputra. The agitation originated years back. It is not that the Bodo issue was started recently. There was an agitation for the recognition of their language. There was an agitation for the economic uplift of the Bodo people. The Government rightly signed the Accord with the agitationists and gave them the Bodo Autonomous Council to bring all-round development in the Bodo autonomous areas and to the people who are connected with it. But, unfortunately, after the Accord, four major incidents have taken place and they have resulted in this massacre. It is very unfortunate that we have to say that there are mistakes. At one point of time we have to agree that there are mistakes. Three accord have been signed in the North-Eastern part of India in recent years. Out of them, the Mizo Accord, though there is some oppositoin to it, has been functioning successfully. The Assam Accord, though a few points of the Accord are to be implemented fully, has, by and large, been accepted by the people and there is an amount of satisfaction among all sections of the people of Assam. The third accord is the Bodo Accord. The Bodo Accord was signed and with the signing of the Bodo Accord the Bodo Autonomous Council has come up. But there also like the Assam Accord and the Mizo Accord some people remained unhappy with it. Some people did not like the Accord and some people are still opposing the Accord. Why has this Accord been opposed? What is the reasons? The Accord has aroused a lot of hopes and aspirations in the people of that area. They thought that developmental activities would come in a big way and there would be effective economic development and their lot would be improved. But unfortunately, the Bodo Autonomous Council which came into effect could not function effectively because of differences among the Bodo leadership.

Madam, I don't want to defend anybody here. But I must say that the Bodo Autonomous Council which came into effect due to the agitation, due to the accord, doesn't have the teeth to implement the economic development programmes. It is very sad and I am very unhappy to say that finance, which is the main input for the the developmental work, is very, very scarce with the Bodo Autonomous Council. As a result, they could not put the Bodo leaders together. That is why they have suffered. The hopes and aspirations of the Bodo people could not be met. Madam, it is not the only event. We have to study it. We have to analyse it in the broad perspective of the State and of the region as a whole. It is not that peace was not disturbed earlier. It is not that there were no conflicts earlier. There were conflicts. But, those conflicts were sorted out. Madam, as you know, Assam is a multicultural State. It is a society of assimilation, a society of different languages, a society of different cultures. All the people, tribal and non-tribal, of different cultures and different languages live together and work together for the uplift of that region, of that State. The hon. Member of the Opposition cited some historical facts. She said that it was all due to the failure of the policies of the Congress. Madam, the demand for the Bodo Autonomous Council is not new. She mentioned that during the time of the late Pandit Jawaharlal Nehru, who was the architect of modern India, autonomy was offered to them. The Bodo people, the tribal people were told that they could have their autonomous district. But, the nationalist leaders of the State and the Bodo leaders said, "We are Assamese and the whole State belongs to us, not one district." Madam, these were

[Shri Bhuneshwar Kalita]

the sentiments, these were the emotions of the people of Assam at that time. How has it been disturbed?

I would like to mention one fact, i.e. the economic backwardness. The economic backwardness has given rise to all these problems. Madam, I don't know why all the problems are in the north bank of the Brahmaputra and why all the problems are in the lower parts of Assam, be it a foreign national issue, be it a Bodo issue or any other issue. The people living there are economically backward. Madam, do you know for how much you can have daily labourers? You can get daily labourers even for Rs. 5/-. They will work for 12 hours. This kind of economic backwardness we have in the lower parts of Assam. People say that all the problems are in the lower parts of Assam and prosperity is outside Assam. Until and unless, this part of the State, this part of the region, is developed economically, these problems will remain because there is constraint of resources. There are very little resources. The issue is not of any culture or any language today. The issue is one of fight for economic development. Until and unless you improve the economic contions in that part of the country, in part of the State, the issue will remain there, the issue will remain alive.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Kalita, we have to adjourn the House for lunch. Your party has got time. So, you can continue your speech after lunch.

The House is adjourned for one hour for lunch.

The House then adjourned for lunch at thirty one minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at thirty-two minutes past two o the clock, The Vice-Chairman (Mis Saroj Khaparde) in the Chair.

Short duration discussion—Contd.

Serious situation in Assam in view of recent ethnic clashes and massacre of refugees in Barpeta district - Contd.

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): Shri Bhubaneswar Kalita to continue the discussion

SHRI BHUBANESWAR KALITA: Madam, before lunch, in today's discussion, I had raised the matter of economic backwardness as the root cause of the present turmoil in Assam and elsewhere. Particularly, this is the effect, this is the net result, in Barpeta and other areas. Madam, the area which was affected, the area where the massacre has happened the area which has to undergo such a turmoil, is not an ordinary area, is not an area where clashes happened earlier or have been happening all the time. Madam, this is the area, the people of which have fought all the external aggressions. The people of this area lived in communal harmony, lived a emotional unity. It is that communal harmony, it is that emotional unity which combined them together in fighting the Mughals, in fighting the Britishers. Madam, the people of this area saved the entire north-eastern region from going under the external subjugation. Till 1828 the whole of this area was ruled by its own people. It never came under any external subjugation. The people of this area never allowed the external aggressors to go over to the other bank of the Brahmaputra. Madam, what has happened to that harmony, what has happened to that unity? Today, there are conflicts in the minds of the people, there are disturbances in the minds of the people, the root cause of which is the economic backwardness, and it is not anything else.

Madam, as I have mentioned in my pre-lunch speech, if you all remember, in 1947, there were communal

clashes all over the country except in Assam. Madam, this was the unity, this was the harmony in Assam. When the whole of the country experienced communal clashes in 1947, Assam was peaceful. There was not a single communal clash, not even a single Hindu, died, not even a single Muslim died there, And such was the spirt of the area, such was the spirit of the region, such was the spirit of the people of that area which brought glory to the people of that area, glory to this country.

Madam, the hon. Member of the Opposition raised some questions. He has blamed that some of the policies of the Congress Party as the root cause of this tribal backwardness. Madam, I feel sorry about it. It is the Congress which has brought unity and harmony in that part of the country. It has not only brought unity and harmony, but it has also maintained that unity and harmony. And I should not mention what had happened in 1979 and 1987. I do not want to blame any party. This is not the forum, this not the time to blame each other. This is the time to bring peace to that part, this is the time to think about those people, to think about those hapless lot who have given their ot and who have died in the massacre. Madam, giving a political colour to it will be the most unfortunate thing because death and misery to anybody, to any Hindu or any Muslim, to any community cannot be a political issue and cannot be given a political colour because death is a death and miseryy is a misery.

Madam, if you go back to what happened in 1979 and 1987, everything will be clear to the Members, to the august House as to how the situation had erupted, how these problems were created and how these problems were nurtured. And today, you blame the policy of the Congress Party which has really given the economic upliftment, the motto of which is to bring up these tribals and non-tribals and the downtrodden people of this country.

Madam, one important factor in the present situation in the North-East is the crisis of ethnic identity. In the past, the harmony was maintained by an understanding of the broad society, the understanding of the broad society enunciated by the people, by the social workers, by the politicians, which has put all the communities together, all the sections together in that part of the country. But the economic backwardness has given rise to the individual identity, and finally the crisis of ethnic identity has come up. Today, because the resources are scarce, the inputs of development are scarce, there are clashes there are conflicts, and this has to be taken into consideration very seriously by the Govrenment.

But while finding a solution to this crisis, to this turmoil, if we go for a short-cut, it would prove counter-productive. It has to be a long-term solution. There has to be a well-thought-out plan in this regard. If we go for a short-cut, the present turmoil may get aggravated.

There has been a reference here as well in other outside fora to the question of autonomy. But to my mind, autonomy, by itself, cannot solve the problem until and unless we provide teeth to it. We have given autonomy in the case of some areas. But as I said, just by giving autonomy we cannot solve the problem. We have to really give a serious thought to it as to what else should be done to make it more effective.

Madam, today, the situation there has become almost normal. There were no incidents on the 21st and the 22nd. The security forces have taken over. However, there remains the problem of resettlement of the 60,000 refugees who are now sheltered in th various camps. The Government should immediately take steps to enable these people to go back to their places and resume their normal life. The Government should also ensure their full protection in the villages after they go back

[Shri Bhubaneswar Kalite]

Then, the Government cannot remain silent about the extremists who have indulged in this massacre. We know where these extremists are hiding after committing this worst-ever crime. It is known to the Home Ministry, it is known to all of us, that these extremists have taken refuge in neighbouring Bhutan. The Government has to do something in this regard so that these exit points are plugged properlyn. The Government should see that the extremists are not able to run away after commiting such crimes.

I have another suggestion to make to the Government. If the Government has the will—I hope it has—it should review the Bodoland Accord. Of course while reviewing the accord, the Bodo leaders should be taken into confidence. At the same time, the interests of the non-Bodos should also be kept in mind because, as everybody knows, in the B.A.C. areas, the non-Bodos are in larger number than the Bodos. Therefore, the interests of the non-Bodos in these areas should be fully protected. For this purpose, the Government should review the accord and make amendments in it if necessary, after taking into confidence the Bodo leadership.

As I mentioned earlier, the economic backwardness of the lower part of Assam should be gone into very seriouly. Until and unless this aspect is taken care of, the basic problem would remain. We may tide over the situation for the present, but the basic problem would still remain. For that I had suggested undertaking an economic survey of the lower part of Assam, which is the most backward area economically to ensure its uplift.

I want to say one more thing. Some military action is going on there. You know military action is always counter-productive and it creates some other problems. So, it should be for as short a period as possible. And we should give leadership to the peace committees, which are being formed and make them more functional to bring peace to those areas.

We have entered into an accord with the Bodo leadership. There may be some differences among the Bodo leaders; but we should not discredit them. Otherwise, the extremists will take over. The Government should rather give support to the moderate leadership in financial and political terms in order to make them effective. These people are the buffers in the solution of the problem. So, they have to be made effective and financial and it has to be ensured that leadership remains with them. Otherwise, extremists will take over and more such incidents will happen. So, I request the Government to take some concrete, serious steps and it should not appear that it is delaying action; which will give rise to more problems. With these words I conclude.

श्री विष्णु कांत शास्त्री (उत्तर प्रदेश) : महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय सदन का और भारत सरकार का विशेषकर गृह मंत्रालय का ध्यान बरपेटा में घढी हुई दुर्घटना के पीछे के कारणों की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं । यह बिल्कुल स्पष्ट है कि बरपेटा में जो कुछ घटा, है वह अत्यंत ग्लानि जनक है । शरणार्थियों के शिविर पर अंधाधुंध गोली चलाकर बच्चों और महिलाओं को मारना ऐसा जघन्य कार्य है जिसके द्वारा केवल सरकारों के ऊपर नहीं, हमारे देश के ऊपर भी कलंक का टीका लग गया है। मैं इस घटना की निंदा करता हूं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से । लेकिन यह चाहता हूँ कि ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो । इसलिए इसके मूल कारणों की ओर ध्यान दिया जाए । इन दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार कौन है ? क्या वे आतंकवादी हीं इस कांड के लिए जिम्मेदार हैं जिन्होंने उन शरणार्थियों पर अंधाधुंध गोली चलाकर यह दुष्कांड घटित किया या इसके

पीछे वे लोग भी जिम्मेदार हैं जिन्होंने वर्षों लगातार गलत नीतियों के कारण सारे देश की शांति को, उसकी अखंडता को खतरे में डाल दिया ? क्या यह ऐसी पहली घटना घटी है क्या इसपहले असम में इस प्रकार की दुर्घटनाएं नहीं घटी ? मैं इस सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि इसके पहले भी मंदोई में, मेली में और खोकड़ाजार में बिल्कुल इसी प्रकार की घटनाएं घटी थी । क्या उन घटनाओं के कारणों पर विचार किया गया? क्या -उन कारणों के निवारण का कोई प्रयास किया गया और अगर उन कारणों को जानकर भी हमने उन कारणों के उन्मूलन की ओर कोई ठोस कदम नहीं उठाए, उनकी तरफ से आंख मूंदे रहे तो क्या इतिहास हमको क्षमा करेगा ? म आपको याद दिलाना चाहता हूं कि देश के विभाजन की अध्यक्षता करने वाले लार्ड माउंटबैटन के ऊपर भी आज इतिहास अपना कड़ा फतवा दे रहा है। प्रमाणिक तथ्यों के आधार पर इतिहास-कार बता रहे हैं कि लार्डमाटबैटन की जल्दबाजी के कारण उनकी गल्तीयों के कारण लाखों आदमियों की हत्याएं हुई, करोड़ों आदमी घनघोर वेदना से गुजरे और उन्होंने कहा कि लार्ड माउंटबैटन का इम्पीचमेण्ट होना चाहिए था उन पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए था उनको सजा दी जानी चाहिए थी। यह बात केवल लार्ड माउंटबैटन के लिए सच नहीं है, यह बात उन तमाम शासकों के लिए सच है, हमारे आज के शासकों के लिए भी सच है जो आंख मूंदकर उन घटनाओं को घटने दे रहे हैं जो हमारे देश के लिए कलंक का स्वरूप है और उनके कारणों की ओर ध्यान नहीं देते हैं । मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि जब पहली घटना इस प्रकार की घटी तो उस घटना के घटने के बाद हमारी तत्कालीन प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने वहां कांग्रेस के उच्च नेताओं को भेजा था जिनका नेतृत्व श्री दिनेश सिंह ने किया था कि वे वहां जाएं और इस बात की जांच करें कि मंदोई जिले में इस प्रकार के हत्याकांड क्यों घटे और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि उन्होंने यह भी कहा था कि केवल कानून और व्यवस्था की ओर नहीं बल्कि सामाजिक कारणों की ओर, राजनीतिक कारणों की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए । वहां से लौटकर श्री दिनेश सिंह जी ने जो रिपोर्ट दी थी, उस रिपोर्ट का मुद्दा, मूल मुद्दा यह था, उन्होंने बताया था कि वहां सीमा पार से अर्थात् बांग्लादेश से आए हुए बड़ पैमाने पर घसपैठिए बसे हैं जिन्होंने जनजातियों की जमीन पर कब्जा कर लिया है और विदेशियों द्वारा कब्जा करने के कारण वे जनजाति के लोग विक्षुब्ध होकर इस प्रकार का काण्ड करने के लिए अग्रसर हुए हैं । मैं जानना चाहता हूँ कि श्री दिनेश सिंह ने जो बात बतायी थी, उस पर क्या अमल किया गया है ? क्या सचमुच जनजातियों की जमीन पर कब्जा करने वाले बांग्लादेशी घुसपैठियों को विताड़ित किया गया ? क्या उनकी जमीन उनको वापिस दिलायी गयी ? क्या उन घुसपैठियों को चिन्हित किया गया ? क्या उनको बांग्लादेश वापिस भेजने के लिए कोई ठोस कदम उठाया गया ? यह बात 1981 की है और 1981 में जो बात नहीं हुई वह आज 1994 में भी नहीं हो रही है, इससे बढ़कर पीड़ा की बात और क्या हो सकती है । मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 1992–93 में हमारे गृह मंत्रालय ने असम की स्थिति के बारे में जो प्रतिवेदन दिया है, उस प्रतिवेदन में हमारे गृह मंत्रालय ने कहा है कि पूर्व पाकिस्तान अधुना बांग्लादेश से बड़े पैमाने पर होने वाले जन-संक्रमण के कारण स्थानीय निवासियों को लगता है कि वे देश अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं । पूर्वांचल के अर्थनीतिक ढांचे पर भी इस जनसंक्रमण ने गहरा प्रभाव डाला है। इसके द्वारा देशवासियों की एकात्मता को गहरी चोट लगी है, उनके जातीय एवं दलीय संघर्षों की दृष्टि से । यह भारतीय जनता पार्टी की रिपोर्ट नहीं है । यह भारत सरकार के केन्द्रीय गृह मंत्रालयज का 1992–93 का प्रतिवेदन है और मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इस प्रतिवेदन का प्रत्याख्यान करते हुए असम के मुख्य मंत्री श्री हितेश्वर सैकिया ने कहा कि यह बिल्कुल गलत रिपोर्ट है और उन्होंने

[श्री विष्णु कांत शास्त्री]

कहा कि असम में कोई घुसपैठिये नहीं हैं। यह चमत्कारपूर्ण वक्तव्य उन्होंने 18 मई, 1992 को दैनिक पत्र टेनल को दिए हुए अपने साक्षात्कार में दिया। मैं याद दिलाना चाहता हूं सदन को कि यह वही श्री हितेश्वर सैकिया हैं जिन्होंने 30 अप्रैल, 1992 को असम की विधान सभा में कहा कि केवल 1987 से 20 लाख से 30 लाख तक बांग्लादेश के घुसपैठिए असम में आए हैं। यह वही हितेश्वर सैकिया हैं जिन्होंने होमेन बड़-गोहाई के साप्ताहिक पत्र 'नागरिक' में लख लिखते हुए बड़े विस्तार से इस बात को प्रमाणित किया था कि किस प्रकार लगातार बांग्लादेश से घुसपैठिए चले आ रहे हैं और उन्होंने यह बताया था कि वे मैमनसिंह से उम्मेला से ढाका से आ रहे हैं। उन्होंने बताया था कि ये घुसपैठिए नौगांव में, उत्तर लखीमपुर में, ग्वालपाड़ा आदि जिलों में बस रहे हैं। वही हितेश्वर सैकिया जो इस बात का दावा करते थे कि तमाम घुसपैठियों को बाहर निकालना चाहिए, वही हितेश्वर सैकिया 10 अप्रैल, के अपने वक्तव्य को नकारते हुए 18 मई को दूसरे प्रकार का वक्तव्य देते है क्योंकि इस बीच में उन को धमकी दी गई थी कि अगर घुसपैठियों के बारे में इस प्रकार का वक्तव्य देंगे, इस प्रकार की बात करेंगे तो मुख्य मंत्री की उनकी गद्दी सुरक्षित नहीं रहेगी। अपनी गद्दी को बचाने के लिए उन्होंने अपने लिखित लेखों को, अपने वक्तव्यों को और स्वयं गृह मंत्रालय के प्रतिवदन को झुठला दिया। इसी को कहते हैं —

जैसा मौसम हो, मुताबिक उसके मैं दीवाना हूं,

मार्च में बुलबुल हूं मैं, अप्रैल में परवाना हूं।

अगर आपको यह बताने का मौका मिलता है कि ये जो घुसपठिए हैं इन को निकाल देंगे, अगर इस तरह के वक्तव्य से आप को वोट मिलते हैं तो आप कहिए कि 20 लाख घुसपैठिए एक साल में आए। अगर आप की गद्दी सुरक्षित रहती है यह कहकर तो आप कहिए कि असम में एक भी घुसपैठिया नहीं है और हमारी सरकार ने जो प्रतिवेदन दिया है वह असंभव है। मैं माननीय गृह मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने अपने असम के दौरे में कहा कि यहां पर बहुत घुसपैठिए आए हुए हैं। जिनके कारण असम की समस्या जटिल हो गई है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या गृह मंत्री का घुसपैठियों के बारे में यह वक्तव्य सही है या .... **(व्यवधान)**

मौलाना ओबैदुल्ला खान आज़मी (उत्तर प्रदेश) : यह तय तो हो कि झूठ कौन बोल रहा है ....

†مولانا عبید اللہ خان اعظمی (اتر پردیش) : یہ طے تو ہو کہ جھوٹ کون بول رہا ہے ....

श्री विष्णु कांत शास्त्री : उन्होंने तो पहले कह दिया था कि 30 लाख से ज्यादा घुसपैठिए आ गए हैं। यह चमत्कार कैसे हो गया। यह चमत्कार केवल केन्द्रीय गृह मंत्रालय को दोषी नहीं ठहराया है यह चमत्कार असम के मुख्य मंत्री के चरित्र को भी उजागर करता है जो कुछ देर के बाद अपने वक्तव्य को बदल सकते हैं।

महोदय, मैं बहुत पीड़ा के साथ ये बातें कह रहा हूं। मैं समझता हूं कि असम की समस्या एक राष्ट्रीय समस्या है। इस को दलीय दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए मैंने आरम्भ में इस दुर्घटना का पूरी निन्दा की। मैं पीड़ा के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी समझ और संकल्प के साथ उस मंतव्य को दोहराना चाहता हूं जिसके कारण इस प्रकार की घटनाओं का घटना असंभव हो जाए। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि हम जब तक इस प्रकार के अंधाधुन्ध चले आने वाले घुसपैठियों को रोकने का प्रभावी कदम नहीं उठाएंगे तब तक इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति होती रहेगी जैसी मंदोई, नेली कोकराझाड़ और बरपेटा

†[ ]Transliteration in Arabic Script.

में हुई । मैं यह भी बताना चाहता हूं कि श्रीमती इंदिरा गांधी के समय 1981 में जो घटनाएँ घटीं थीं उससे अब कई और पेंचबढ गए है। 1981 में आइ०एस०आइ० का इतना बड़ा जाल नही फैला था उस के बाद 1981 से आज 1994 में आइ०एस० आइ० ने न केवल सारे भारत वर्ष में बल्कि विशेष रूप से देश के पूर्वांचल में अपने जाल को बहुत सघनता के साथ फैलाया है । वहां पर उन्होंने इस प्रकार की चेष्टाएं की हैं कि तमाम आतंकवादी बंगला देश से प्रशिक्षित होकर वहां आएं । मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ यह कह रहा हूं कि बंगला देश की भूमि पर तमाम पूर्वांचल के उग्रवादियों को प्रशिक्षित किया जाता है । आइ. एस. आइ. उनको न केवल प्रशिक्षण देता है बल्कि उनको हथियार भी देता है, उनको अर्थ भी देता है, उनको पैसा भी देता है और बराबर उनको प्रेरणा देता है कि वे इन क्षेत्रों में आग भड़काते रहें और भारत के टुकड़े-टुकड़े करने की कोशिश करें । मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, पश्चिमी बंगाल और बिहार में भी इस प्रकार की साजिशें चल रही हैं । मैं आप को सावधान करना चाहता हूं कि विशेषकर सिलीगुड़ी अंचल में आइ. एस. आइ. ने जो अपना जाल फैलाया है उनकी यह चेष्टा है कि सिलीगुड़ी में इस प्रकार की आग जलाई जा सके जिससे कि पूरा पूर्वांचल भारत भूमि से कट जाए ।

3.00 P.M.

सिलीगड़ी के उस छोटे से अंचल से होकर हमारी तमाम रेलें आती-जाती हैं । यह सिलीगुड़ी अंचल प्रभावित किया जा सके इसकी पूरी चेष्टा आई. एस.आई. वाले कर रहे हैं । यदि वे सफल हुए तो हमारा यह पूर्वांचल हम से, जमीन से कट जायेगा । मैं जानना चाहता हूं हमारा गृह मंत्रालय आईएसआई के इन कुचक्रों के प्रति कितना सावधान है ? वह उनके षडयंत्र को विफल करने के लिये क्या प्रभावी कदम उठाने जा रहा है ? मैं यह भी बताना चाहता हूं कि 1981 में श्री दिनेश सिंह ने यह बताया कि मूलभूत समस्या बांगला देश से आये हुये गैर जनजाति के लोगों के द्वारा जनजातियों की भूमि पर कब्जा करने की है । इससे भी दूसरी बड़ी उलझन पैदा होती है आतंकवाद की । आतंकवाद के संबंध में कुछ मित्र कहते हैं कि यह केवल भ्रांति का सवाल है । अभी हमारे मित्र कालिता जी कह रहे थे क्योंकि वहां आर्थिक विकास नहीं हुआ है इसलिये आर्थिक विकास की आवश्यकता है । मैं यह मानता हूं कि उत्तर पूर्वांचल में जितना आर्थिक विकास होना चाहिये, उतना नहीं हुआ । मैं इसके लिये भी कांग्रेस सरकार को दोषी ठहराता हूं । लेकिन मैं यह भी बताना चाहता हूं कि जो अपने भोलेपन के कारण केवल आर्थिक विकास की अवरुद्ध स्थिति की, आर्थिक दृष्टि से अविकसित स्थिति को आतंकवाद का मूल कारण मानते हैं वह बहुत बड़ी गलतफहमी में है । क्या कारण है पंजाब जो आर्थिक दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा आगे बढ़ा हुआ राज्य था उसमें इतना बड़ा आतंकवाद अपना खूनी सिर उठा सका, अपना खूनी पंजा जमा सक है । क्या कारण है कि उड़ीसा जो भारतवर्ष में सबसे गरीब राज्य है वहां आतंकवाद नहीं है । इसलिये केवल आर्थिक विकास की समस्या को आतंकवाद के साथ जोड़ा जाय यह एक बहुत बड़ी गलती है जिससे हमें बचना चाहिये । इस आर्थिक विकास के लिये पूरी ताकत से वकालत करते हुये भी मैं यह बताना चाहता हूं कि इसका मूल कारण कहीं और है । वे विदेशी शक्तियां, वे विदेशी ताकतें जो हमारे देश को टुकड़ों में बांट देना चाहती हैं वह अपना खूनी पजा, वह अपना खूनी षडयंत्र हमारे देश पर लागू करना चाहती है इसलिये वह हमारे नौजवानों को बहकाते हैं, कहीं क्षेत्रीयता के नाम पर, कहीं जनजाति के नाम पर, कहीं धर्म के नाम पर । मैं यह बताना चाहता हूं कि इन विदेशी शक्तियों के मंसूबे को कुचल देने के लिये जैसी तैयारी हमारी होनी चाहिये वैसी तैयारी हमारी नहीं है । इसका सबसे बड़ा दर्दनाक और सबसे बड़ा दयनीय उदाहरण असम है । असम में जब उल्फा ने, युनाइटेड लिबरेशन फ्रंट आफ असम ने अपना खूनी सिर उठाया और जब हमारी फौजों ने सफलतापूर्वक उनका सफाया किया तो इन्हीं मुख्य मंत्री जी ने बढ़ती हुई

[श्री विष्णु कांत शास्त्री]

फौजों को रोक दिया और रोक कर उन्होंने एक नया विधान चलाया। उन्होंने उल्फा की जगह सल्फा को जन्म दिया। उन्होंने बताया कि उल्फा के लोग आत्म-समर्पण करना चाहते हैं। जो उल्फा के लोग आत्मसमर्पण करेंगे उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिये हम आर्थिक सहयोग देंगे। इस आर्थिक सहयोग के नाम पर इतना बड़ा भ्रष्टाचार पूर्वांचल में चल रहा है जिसको देखकर शर्म आती है। मैं यह बताना चाहता हूं कि पूर्वांचल की बड़ी समस्याओं में एक बहुत बड़ी समस्या उसके कण-कण में, उसके रंध्र-रंध्र में छाया हुआ भ्रष्टाचार है। मैं पुनः अपने माननीय गृह मंत्री चव्हाण जी का अभिनन्दन करता हूं कि उन्होंने अपने पिछले वक्तव्य में यह स्वीकार किया कि पूर्वांचल की एक बहुत बड़ी समस्या भ्रष्टाचार की समस्या है। यह भ्रष्टाचार की समस्या आतंकवाद के साथ कैसे जुड़ती है इसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह बहुत ही पीड़ा की बात है कि इन्हीं मुख्य मंत्री जी ने यह घोषित किया कि जो उल्फा के कार्यकर्ता थे वह अब समर्पण करके मुख्य धारा में मिलना चाहते हैं उनको लाखों रुपये का लाभ दिया जायेगा। वास्तविक उल्फा के लोगों को उसका अधिक लाभ नहीं मिला। मैं बिल्कुल अधिकार के साथ और प्रामाणिकता के साथ यह बताना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी ने अपने लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को उल्फा के कार्यकर्ताओं के रूप में प्रस्तुत किया। उनसे समर्पण कराया और उनको सल्फा के नाम पर सरन्डर उल्फा के नाम पर आगे बढ़ाया। इस तरह से अपनी एक फौज खड़ी की जिसके द्वारा वे अपने विरोधियों को पिटवाते रहते हैं। जिसके द्वारा वे अपने विरोधियों के ऊपर आक्रमण करवाते हैं और यह बात इन्होंने भी सीखी। नागालैंड तथा मनीपुर में भी एक-एक उग्रवादी को दो-दो लाख रुपये का प्रलोभन देकर उनको वापस लाने की चेष्टा की गई जो कांग्रेस सरकार एक-एक करोड़ रुपये में सांसदों को खरीद सकती है, उसी पार्टी की सरकार वहां पर इसी प्रकार से लाखों की संख्या में तथाकथित उग्रवादियों को अपनी तरफ लाने का षडयंत्र कर रही है। मैं कहना चाहता हूं कि इससे देश को सावधान होना चाहिये और समझना चाहिये कि किस अनर्थ की ओर हमारी सरकारें हमको पूर्वांचल में ले जा रही हैं। मैं बहुत ही क्षोभ के साथ यह बताना चाहता हूं कि यह कोढ़ में खाज की तरह है कि हमारी यह जो स्थानीय समस्यायें हैं ये आई. एस.आई. के कारण, उग्रवाद के कारण, भ्रष्टाचार के कारण बढ़ती जा रही हैं। हमारा प्रत्युत्तर इसके लिये क्या है? हम दृढ़ता के साथ इन समस्याओं का समाधान करने के लिये जो कदम उठा सकते हैं वे कदम भी नहीं उठा रहे हैं।

आखिर में मैं कहना चाहता हूं कि बोडो समझौता या असम समझौता जो हुआ उसका पालन नहीं किया गया। क्या उसको पूरी तरह कार्यान्वित किया गया ? यह बताया गया था कि जो 1971 में 25 मार्च के बाद जो लोग बांगला देश से आये हैं उनको निकाल बाहर किया जायेगा क्या किसी को बाहर निकाला गया ? क्यों नहीं ऐसा किया गया ? जो समझौता किया जाता है उसका अगर पालन न किया जाय तो वह नयी-नयी समस्याओं को जन्म देगा। इसलिये मैं समझता हूं कि ये तमाम कारण इसके लिये जिम्मेदार हैं।

एक बात और मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। आजादी के बाद जो असम का मानचित्र था उसको दृष्टि में लाइये और वर्तमान मानचित्र जो असम का है, उसको भी दृष्टि में लाइये और सोचिये कि असम के कितने टुकड़े हुये ? ये टुकड़े जनजातियों के नाम पर किये गये, ठीक है लेकिन इसकी कोई सीमा होनी चाहिये। अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि बोडो लैंड में जो भूमि दी गयी उसमें जितने बोडो हैं उनसे ज्यादा गैर-बोडो हैं। वहां के मुख्य मंत्री ने तमाम जनजातियों को आश्वासन दिया है कि उनको स्वायत्तता दी जायेगी। अगर इस प्रकार से स्वायत्तता देने का भ्रम फैलाया जायेगा तो उसका परिणाम

क्या होगा ? स्वायत्ता देकर उनके वोट खरीद कर आपकी सरकार तात्कालिक रूप से बच सकती है, तत्कालिक रूप से आपकी गद्दी सुरक्षित रह सकती है लेकिन दीर्घकालीन दृष्टि से देश को इससे कितनी हानि होगी, आपकी दुर्नीतियों के कारण, इस पर आपको विचार करना चाहिये । मैं यह भी बतलाना चाहता हू कि यह जो दुर्घटना हुई, यह अकारण नहीं हुई है, इसके पीछे कुछ उत्तेजक कारण थे वे क्या हैं ? उन उत्तेजक कारणों के बारे में मैं चाहता हूं कि माननीय गृह मंत्री जी स्पष्टीकरण दें इन उत्तेजक कारणों के संबंध में जो वहां के नेताओं ने जो आरोप लगाये हैं वे रोमांचक हैं यह बताया गया है कि इस उत्तेजक कांड के पीछे असम के पशुपालन मंत्री हैं, श्री शम्सुल हक, उनके भाई बाबल हक और सिद्दीकी अली हैं । पुलिस के ऊपर हुए आक्रमण का प्रतिवाद करने के लिये वे पुलिस के साथ वहां गये और उन्होंने बोडो गांवों को लूटा, उन्होंने बोडो महिलाओं को अपमानित किया, उन्होंने बोडो महिलाओं को नंगा करके घुमाया और उन्होंने बोडो स्कूलों के ऊपर आक्रमण किया। उन्होंने बोडो बच्चों की किताबें भी जलाई और बोडो बच्चों के ऊपर अत्याचार किया । क्या यह सच है यह मैं जाना चाहता हू ? यहां पर हमारे रक्षा राज्य मंत्री उपस्थित हैं । यह आरोप कि शम्सुल हक के नेतृत्व में पुलिस ने वहां पर अत्याचार किया क्या यह सच है ? शम्सुल हक के नेतृत्व म कांग्रेस के लोगों ने, जिनमें ज्यादा लोग वे थे जिनको स्थानीय लोक सीमा पार का मानते हैं, जिनको वहां के लोग घुसपैठिया मानते हैं, उन लोगों ने 13 जुलाई को बोडो गांवों के ऊपर अत्याचार किये ? क्या वहां जो क्रर कांड हुआ, जो वहां आग लगाई गई, महिलाओं को वहां पर नंगा किया गया, महिलाओं को अपमानित किया गया, उसमें उन लोगों का हाथ था ? अगर यह सच है तो फिर उसकी यह जो परिणिति हुई जो कुछ वहां हुआ है उसकी भी हम घोर निंदा करते हैं । लेकिन मैं एक बात आपके सामने कहना चाहता हूं कि जो दुर्घटना अभी घटी है, केवल उसकी निंदा करना या उसके ऊपर अपना क्षोभ प्रकट करना यह कोई बड़ी बात नहीं है । बारपेटा में जो हुआ है, वह बीमारी नहीं है, वह बीमारी का लक्षण है । बीमारी के लक्षण को बीमारी समझना गलत काम होगा । जो मूल बीमारियां हैं, जिन मूल दुर्नीतियों के कारण, गलत नीतियों के कारण, लंबी उपेक्षाओं के कारण अत्याचार हुये हैं, अन्याय हुये हैं, मूलतः वे इसके लिये जिम्मेदार हैं । जिन नेताओं ने, जिन मुख्य मंत्रियों ने, जिन गृह मंत्रियों ने और जिन प्रधानमंत्री जी ने इन नीतियों को समर्थन दिया है, वे इसके लिये जिम्मेदार हैं । आज अपने बहुमत से वे जरूर अपनी इज्जत बचा सकते हैं लेकिन जिस प्रकार माऊंट बैटन के ऊपर इतिहास ने फतवा दिया था, उन पर भी इतिहास फतवा देगा । मैं यह मांग करता हूं अपनी पार्टी की तरफ से कि इस भ्रष्ट और अयोग्य मुख्य मंत्री को बर्खास्त किया जाय । हम भारतीय जनता पार्टी के लोग किसी भी चुनी हुई सरकार को बर्खास्त करने में विश्वास नहीं करते हैं लेकिन स्थिति यहां तक चली गई है कि इसके बाद इसको झेलना देश के लिये अकल्याणकर होगा । इसलिये मेरी और मेरी पार्टी की मांग है कि मुख्य मंत्री को बर्खास्त किया जाये और इसके साथ साथ वे तमाम कदम उठाये जायें जिनसे समस्या का स्थाई समाधान हो सके । उन कदमों के लिये मैं मांग करता हूं पूरे पूर्वांचल में सचित्र परिचय पत्र दिये जायें । बिना सचित्र परिचय पत्रों के कौन इस देश का है और कौन बाहर से आया हुआ है, कौन घुसपैठिया है, उसकी पहचान नहीं हो सकती है । मैं यह मांग करता हूं कि 25 मार्च, 1971 के बाद जो घुसपैठिये आये हैं, उनको निकाला जाय और जो शरणार्थी आये हैं उनको संरक्षण दिया जाये और वहां उनको बसाने की सुविधा देने की चेष्टा की जाये । मैं यह मांग करता हूं कि आई०एस०आई० के षडयंत्र को बेनकाब किया जाये, विफल किया जाये, आतंकवाद का दमन किया जाये । मैं यह भी मांग करता हूं कि समस्त उत्तर पूर्वांचल का आर्थिक विकास करने की योजनायें बनाई जायें । लेकिन

[श्री विष्णु कांत शास्त्री]

बिना इन सब कदमों को उठाये, इस प्रकरण में जिन लोगों ने अत्याचार किया है उन्हीं को दोषी करार देना, उन्हीं के बारे में बड़े बड़े व्याख्यान देना कोई अर्थ नहीं रखता। इस बीमारी की जो असली जड़ है, मूल जड़ है जब तक उसको नहीं उखाड़ा जाता तब तक उस प्रकार के हादसे घटते रहेंगे जैसा हादसा मंदोई में घटा, नेली में घटा, कोकराझार में घटा और अब बारपेटा में घटा, इसकी पुनरावृत्ति न हो, यह सभी चाहते हैं पर जब तक आप और हम सब मिल कर इसके जो आधारभूत कारण हैं जब तक उन कारणों को दूर नहीं करते तब तक इस प्रकार की घटनाओं को रोक नहीं सकेंगे। अन्त में अभी जो दुर्घटनायें घटी हैं उनकी निंदा करते हुये जो इसके लिये जो जिम्मेदार हैं उन सब को दंडित करने की मांग करते हुये, महोदया, आपको धन्यवाद देते हुये मैं अपना व्याख्यान समाप्त करता हूं।

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे) : धन्यवाद शास्त्री जी। मौलाना ओबैदुल्ला खान आजमी।

मौलाना ओबैदुल्ला खान आजमी : शुक्रिया मैडम वाइसचेयरमैन। मैं इस वक्त अपनी पार्टी की तरफ से बारपेटा आसाम में 9 जुलाई को मकामी बाशिन्दों पर मुसीबत के जो बादल गहराये और 23 जुलाई तक हैवानियत दरिन्दगी हिन्दुस्तान में रहने वाले मजलूम इंसानों का कत्लेआम होता रहा, सुबाई हुकूमत और मरकजी हुकूमत की नाकामयाबियों पर जबरदस्त रजोगम का इजहार करता हूं। मोतरमा वाइसचेयरमैन साहेबा, 19 जुलाई को वारदात शुरू हुई, 21 जुलाई, को कयामत टूट गई। तबाहहाल लोगों को फौज ने राहतकारी के लिये कैम्पों में रखा। अखबारों की इत्तेला के मुताबिक 50 हजार इंसान बेघर हैं और उनके तहफुज की जिम्मेदारी हुकूमत ने अपनी सिर पर ले रखी है। उनके तहफुज के सिलसिले में 25 कैंप कुछ लोगों को राहतरसानी के फरायज अंजाम देने के लिये लगाये गये हैं जिसमें यह मजलूम इंसान अपनी शबोरोज गुजार रहे हैं। तमाम इंसानों के लिये हुकूमत के पास शायद कैंप लगाने के लिये भी मवाके मयस्सर नहीं है वो कुदरत के आसमान को अपनी छत बना कर इस बरसात के जमाने में मुसीबतों के साथ अपनी जिन्दगी के दिन गुजार रहे हैं। बारपेटा में कर्फ्यू भी लगाया गया था और उग्रवादियों को देखते ही गोली मारने का हुक्म भी दिया गया था। हमारे मेंबरान-ए-पार्लियामेंट की बहस की रोशनी में इस बात की भी तसदीक हो गई है कि वहां के गैर मुतमईन लोगों ने हुकूमत से इस बात की शिकायत भी की थी कि हम लोग अभी पनाहगुजीन होने के बावजूद अपने आपको गैर महफूज तसव्वुर करते हैं। होम मिनिस्टर साहिबान भी हमारे वहां गए हैं और तफसीली तौर पर इन हजरात की रिपोर्टें भी शाया हो चुकी हैं। मुझे यह अर्ज करना है कि हिन्दस्तान की सरजमीन किस कद्र आज सोगवार है कि दो-चार महीने भी नहीं गुजर पाते कि मुल्क के किसी न किसी हिस्से में खून की होली खेली जाती है। मादरे वतन की इज्जत ओ-आबरू के मुहाफिज चाहे वे आम इंसान हों, चाहे वह फौज में रहने वाले और पुलिस में रहने वाले कर्मचारी हों या पार्लियामेंट में बैठने वाले वी०आई०पी० हों, हम तमाम लोग मादरे वतन की इज्जत को हमेशा सलाम करते हैं और वतन के एक-एक बच्चे को वतन की आबरू कहकर उसके वकार को सलामत रखने की कोशिश करने में यकीन रखते हैं। मगर क्या बात है, वह कौन सी कमजोरी है या हमारे हुक्काम की वह कौन सी मजबूरी है कि मादरे वतन के बच्चे बेरहमी के साथ मारे जाते हैं, मादरे वतन की बेटियों की इज्जत-ओ-आबरू बेरहमी के साथ लूट ली जाती है नन्हें बच्चे यतीम बना दिए जाते हैं, बूढे मां-बाप की निगाहों के सामने

उनके नौजवान बच्चों की लाशें तड़पने लगती हैं । हम एक तरफ मुत्तहदा हिन्दुस्तान का ख्वाब देखते हैं, एक तरफ कौमी सलामती पर यकीन रखते हैं, एक तरफ सैकुलरिज्म और सोशलिज्म की बात करते हैं और दूसरी तरफ मुख्तलिफ हिस्सों में आए दिन फसादात के बादल उठते हैं और नफरतों की बारिश होने लगती है । इन कारणों को समझने के लिए हमारे मुख्तलिफ मैंबरान-ए पार्लियामेंट ने मुख्तलिफ बैंचों से तरह-तरह सुझाव भी दिए हैं । मैं भी इस बात से मुकम्मल तौर पर मुत्तफिक हूं कि हम लोग जो इलाज कर रहे हैं यह इलाज नाकाफी है । उग्रवाद से निबटने के लिए और इलाकाई फसादात से निबटने के लिए हमने जितना भी ज्यादा इकदामात किए हैं, नताइज हमारे सामने आए हैं कि हमारे इकदामात बिल्कुल बेअसर रहे हैं और थोड़े ही दिनों के बाद एक नई घटना घट गई है । कुछ लोग इसे गुरबत करार देते हैं कि गरीबी की वजह से ऐसा हो रहा है, कुछ लोग कहते हैं कि आतंकवाद की वजह से ऐसा हो रहा है, कुछ लोग कहते हैं कि दीन-धर्म के नाम पर ऐसा हो रहा है, कुछ लोग यह कहते हैं कि हकूमत को बचाने के लिए लोग अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए ऐसा करते हैं, मैं यह कहता हूं कि जितनी बातें कही जा रही हैं हर बात फैक्टर बनी हुई है कि इसी की वजह से ऐसा हो रहा है । अगर यह कहा जाए कि उग्रवाद को यह शह मिल रही है इसलिए इस मुल्क की बहू-बेटियों की इज्जतें लूटी जा रही हैं तो इसमें भी कोई शक नहीं है । अगर यह कहा जाए कि मंदिर और मस्जिद के नाम पर इस मुल्क के इंसानों का कत्लेआम हो रहा है और घृणा फैलाई जा रही है तो इसमें भी कोई शक की बात नहीं है। अगर यह कहा जाए कि इलाकाई असबियत का परचम लहराकर हिन्दुस्तान के परचम को सरनगु करने की कोशिश की जा रही है तो इसमें भी कोई शक की बात नहीं है । अगर यह कहा जाए कि फार्वड और बैकवर्ड के नाम पर सियासत की रोटियां सेकी जा रही हैं और हिन्दुस्तानी इंसानों का कत्लेआम हो रहा है तो इसमें भी कोई शक की बात नहीं है । अगर यह कहा जाए कि सत्ता में बने रहने के लिए अपने इकतदार के असूल के लिए, अपने मानने वालों की लाशों पर इकतदार की कुर्सियां रख कर रक्से-इबलीस किया जा रहा है और उसके नतीजे में हिन्दुस्तानियत और हिन्दुस्तान तबाह हो रहा है तो इसमें भी कोई शक नहीं है ।

"एक हंगामाए महशर हो तो उसको भूलूं,
सैकड़ों बातों का रह-रह के ख्याल आता है ।"

इसलिए इसमें मैं यह बात कहना चाहता हूं कि पूरा हिन्दुस्तान देख रहा है मुल्क का एक हिस्सा जला मंदिर और मस्जिद के नाम से, मुल्क के एक हिस्से में बेटियां बर्बाद हुई, मंदिर और मस्जिद के नाम से मुल्क के एक हिस्से में इंसानियत तबाह हुई, धर्म की राजनीति की वजह से तो मुल्क का दूसरा हिस्सा जल पड़ा । सिर्फ सियासी कशमकश की वजह से मुल्क का तीसरा हिस्सा जल पड़ा फार्वड और बैकवर्ड जी लड़ाई के नाम से मुल्क का चौथा हिस्सा जल पड़ा । इलाकाई असबियत के नाम से पांचवां हिस्सा जल पड़ा इलाकाई लैंग्वेज और जुबान के नाम पर, पता यह चला कि ये नफरत ये जितने बुत हैं जब तक ये नहीं तोड़े जायेंगे हिन्दुस्तान की आबरू सलामत नहीं रह सकती

[मौलाना ओबेदुल्ला खान आजमी]

हमारे बच्चों की यतीमी में रोज़-ब-रोज इजाफा होता जाएगा और मादरे वतन की बेटियों को रावण लूटते चल जायेंगे। इसलिए मैं गहरे रंजो-अलम के साथ असम की धरती पर होने वाले इस वाक्या की मजम्मत करते हुए...। हुकूमत के सामने चंद बातें रखकर के अपनी गुफ्तगू खतम करना चाहता हूं। श्री राजेश पायलट जी, जो इस समय इत्तफाक से यहां मौजूद हैं और हमारे मुल्क के जिम्मेदार मोहतरम वजीरे दाखला हैं, मैं उनकी तवज्जोह चाहूंगा। उन्होंने बार बार यह एतराफ किया है और सुबह इस हाऊस में भी उन्होंने फरमाया है कि रियासती इंतजाम में पूरे तालमेल न होने की वजह से यह अफसोसनाक अलमिया आलमे वजूद में आया है। इस इलाके में उस रोज खातिरख्वाह एक तादाद में हिफाजती दस्ते भी नहीं थे। मैं यह कहना चाहूंगा मैडम वाइस चेयरमेन साहिबा, यहां तक हिफाजती दस्तों का मामला है, सौ आदमी आये और जदीद हथियारों से लैस होकर आए, मजलूम निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसा कर चले गए। हुकमत तो कहती है कि 73 लोग मारे गए हैं, मगर हुकूमत हमेशा मरने वालों की लाशों को छिपा कर मरने वालों का डाटा कम पेश करने की पुरानी मजरिम है। पुराने तौर पर इस रस्म को जिंदा रखती है। मैं कहता कि सौ से ज्यादा लोग मारे गए, सौ से ज्यादा लोग घायल हुए, जबकि हमारी तीस तीस गाड़ियां मौजूद थीं और उन तीस गाड़ियों में हमारे सिपाही और कानून के मुहाफिज मौजूद थे? क्या बात है कितने ताकतवर थे वह? कितने जदीद असलाजात से लैस थे वह उग्रवादी कि आकर सौ आदमियों को गोलियों से भूनते हुए निकल गए? उसके बाद हमारी बहादुर फोर्स ने पीछा किया तो सिर्फ दो इंतिहापसंद मारे गए। इस तरह से यह मुल्क की हिफाजत की जाएगी तो मैं तो इतना ही कहूंगा कि—

अगर यही नाखुदा रहगर, अगर यही रहबरी रही,

तो हर किनारे पर आकर किश्ती इसी तरह डूबती रहेगी।

इसलिए मैं मुतालबा करता हूं कि ऐसी सरकार को बने रहने का कोई हक नहीं है, जो मजलूम इंसानों के तहफ्फुज का काम न कर सके। हम दुनियां को क्या मुंह दिखलाएंगे? दुनिया के किसी मुल्क में ऐसा नहीं होता कि पनाहगुजीन इकट्ठे हों। अगर पनाहगुजीन दो, चार, दस, पन्द्रह, बीस, पच्चीस, पचास हजार हों, उनके खाने पीने के इंतजाम में कमी हुई तो यह बात तो समझ में आती है, मगर जान की निगरानी में कमी हुई, यह बात समझ से बाहर है। इसलिए जो लोग मरे हैं, हम उनकी भरपूर खिराजे अक़ीदत पेश करते हुए अपनी हुकूमत से डिमांड करते हैं कि मर्कजी हुकूमत वहां की, असम की हुकूमत को बरखास्त करे और वहां के जो लोग मरे हैं उनके वारिसों को कम से कम दो-दो लाख रुपए फी कस मुआवजे के तौर पर दिए

जाएं और उनके घराने के एक-एक बच्चे को सर्विस में लिया जाए ताकि उनके कुछ दुखदर्द को मुनदमिल किया जा सके। शुक्रिया।

مولانا عبیداللہ خاں اعظمی "اتر پردیش":†
شکریہ۔ میڈم وائس چیرمین۔
میں اس وقت اپنی پارٹی کی طرف سے بارپیٹا آسام میں نو جولائی کو مقامی باشندوں پر مصیبت کے جو بادل گھر آئے اور ۲۳ جولائی تک حیوانیت، درندگی، ہندوستان میں رہنے والے مظلوم انسانوں کا قتل عام ہوتا رہا۔ صوبائی حکومت اور مرکزی حکومت کی ناکامیوں پر زبردست رنج و غم کا اظہار کرتا ہوں۔
محترمہ۔ وائس چیرمین صاحبہ۔ ۱۹ جولائی کو واردات شروع ہوئی۔ ۲۱ جولائی کو قیامت ٹوٹ گئی۔ تباہ حال لوگوں کو فوج نے راحت کاری کے لئے کیمپوں میں رکھا۔ اخباروں کی اطلاع کے مطابق ۵۰ ہزار انسان بے گھر ہیں۔ اور اُن کے تحفظ کی ذمہ داری حکومت نے اپنے سر پہ لے رکھی ہے۔ اُن کے تحفظ کے سلسلے میں ۲۵ کیمپ کچھ لوگوں کو راحت رسانی کے فرائض انجام دینے کے لئے لگائے ہیں۔ جہاں پہ وہ مظلوم انسان اپنی شب و روز گذار رہے ہیں۔ تمام انسانوں کے لئے حکومت کے پاس شاید کیمپ لگانے کے لئے بھی مواقع میسر نہیں ہیں۔ وہ قدرت کے آسمان کو اپنی چھت بنا کر اس برسات کے زمانے میں مصیبتوں کے ساتھ اپنی زندگی کے دن گذار رہے ہیں۔
بارپیٹا میں کرفیو بھی لگایا گیا تھا اور اگروادیوں کو دیکھتے ہی گولی مارنے کا حکم بھی لگایا گیا تھا۔ ہمارے ممبران پارلیمنٹ کی بحث کی روشنی میں اس بات کی بھی تصدیق ہوگئی ہے کہ وہاں کے غیر مطمئین لوگوں نے حکومت سے اس بات کی شکایت بھی کی تھی کہ ہم لوگ ابھی پناہ گزیں ہونے کے باوجود اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کرتے ہیں۔ ہوم منسٹر صاحبان بھی ہمارے وہاں ہیں اور تفصیل طور پر ان حضرات کی رپورٹیں بھی شائع ہو چکی ہیں۔ مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ ہندوستان کی سرزمین کس قدر سوگوار ہے کہ دو چار مہینے بھی نہیں گزر پاتے کہ ملک کے کسی نہ کسی حصے میں خون کی ہولی کھیلی جاتی ہے۔ اور وطن کی عزت و آبرو کے محافظ چاہے وہ عام انسان ہوں چاہے وہ فوج میں رہنے والے اور پولیس میں رہنے والے کرمچاری ہوں چاہے پارلیمنٹ میں بیٹھنے والے ودھایک ہوں ہم تمام تر

†[] Transliteration in Arabic Script.

زیادہ اقدامات کئے ہیں۔ نتائج ہمارے سامنے آئے ہیں کہ ہمارے اقدامات بالکل بے اثر رہے ہیں اور تھوڑے ہی دنوں کے بعد ایک نئی گھٹنا گھٹ گئی ہے۔ کچھ لوگ اسے غربت قرار دیتے ہیں کہ غریبی کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آتنکواد کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دین دھرم کے نام پر ہو رہا ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حکومت بچانے کے لئے لوگ اپنی کمزوریوں کو چھپانے کے لئے ایسا کرتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جتنی باتیں بھی کہی جا رہی ہیں۔ ہر بات فیکٹر بنی ہوئی ہے کہ اس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ اُگرواد کی وجہ سے یہ ہنسا ہو رہی ہے۔ اس لئے ملک کی بہو بیٹیوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں تو اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ مندر اور مسجد کے نام پر اس ملک کے انسانوں کا قتلِ عام ہو رہا ہے اور کھرنا بھیلائی جا رہی ہے تو اس میں بھی کوئی شک کی نہیں ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ علاقائی عصبیت کا پرچم ہر کہ ہندوستان کے پرچم کو سرنگوں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو اس میں بھی کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ اگر یہ کہا جائے

لوگ مادرِ وطن کی عزت کو ہمیشہ سلام کرتے ہیں اور وطن کے ایک ایک بچے کو وطن کی آبرو کہہ کر اس کے وقار کو سلامت رکھنے کی کوشش کرنے میں یقین رکھتے ہیں۔ مگر کیا بات ہے وہ کونسی کمزوری ہے یا ہمارے حکام کی وہ کون سی مجبوری ہے کہ مادرِ وطن کے بچے بے رحمی سے مارے جاتے ہیں۔ مادرِ وطن کی بیٹیوں کی عزت و آبرو بے رحمی کے ساتھ لوٹ لی جاتی ہے۔ ننھے منے بچے یتیم بنا دیئے جاتے ہیں۔ بوڑھے ماں۔ باپ کی نگاہوں کے سامنے اُن کے نوجوان بچوں کی لاشیں تڑپنے لگتی ہیں۔ ہم ایک طرف متحدہ ہندوستان کا خواب دیکھتے ہیں۔ ایک طرف قومی سالمیت پر یقین رکھتے ہیں۔ ایک طرف سیکولرازم اور سوشلزم کی بات کرتے ہیں۔ اور دوسری طرف ملک کے مختلف حصوں سے آئے دن فسادات کے بادل اٹھتے ہیں۔ اور نفرتوں کی بارش ہونے لگتی ہے ان کارنوں کو سمجھنے کے لئے ہمارے مختلف ممبرانِ پارلیمنٹ نے مختلف پہلوؤں سے طرح طرح کے سجھاؤ بھی دیئے ہیں۔ میں بھی اس بات سے مکمل طور پر متفق ہوں کہ ہم لوگ جو علاج کر رہے ہیں یہ علاج ناکافی ہے۔ اگرواد سے نپٹنے کے لئے اور علاقائی فسادات سے نپٹنے کے لئے ہم نے جتنا بھی

† [ ] Transliteration in Arabic Script.

کہ فارورڈ اور بیکورڈ کے نام پر سیاست کی روٹیاں سینکی جا رہی ہیں اور ہندوستانی انسانوں کا قتل عام ہو رہا ہے تو اس میں بھی کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ ستا میں بنے رہنے کے لیے اپنے اقتدار کے حصول کے لیے اپنے ماننے والوں کی لاشوں پر اقتدار کی کرسیاں رکھ کر رقص ابلیس کیا جا رہا ہے اور اس کے نتیجے میں ہندوستانیت اور ہندوستان تباہ ہو رہا ہے تو اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔

ایک ہنگامہ منتشر ہو تو اس کو جھیلوں
سینکڑوں باتوں کا رہ رہ کے خیال آتا ہے

اس لیے اس میں میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ پورا ہندوستان دیکھ رہا ہے ملک کا ایک حصہ جلا مندر اور مسجد کے نام سے۔ ملک کے ایک حصہ میں بستیاں برباد ہوئی۔ اور مسجد کے نام سے ملک کے ایک حصہ میں انسانیت تباہ ہوئی دھرم کی راجنیتی کی وجہ سے تو ملک کا دوسرا حصہ جل پڑا صرف سیاسی کشمکش کی وجہ سے ملک کا تیسرا حصہ جل پڑا۔ فارورڈ اور بیکورڈ کی لڑائی کے نام پر ملک کا چوتھا حصہ جل پڑا۔ علاقائی عصبیت کے نام سے پانچواں حصہ جل پڑا اختلافی لینگویج اور زبان کے نام پر۔ پتہ نہیں کہ یہ نفرت کے جتنے بت ہیں جب تک یہ نہیں توڑے جائیں گے۔ ہندوستان کی آبرو سلامت نہیں رہ سکتی۔ ہمارے بچوں کی یتیمی میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اور مادر وطن کی بیٹیوں کو راون لوٹتے چلے جائیں گے۔ اس لیے میں گہرے رنج و الم کے ساتھ آسام کی دھرتی پر ہونے والے اس واقعہ کی مذمت کرتے ہوئے ..... حکومت کے سامنے چند باتیں رکھ کر کے اپنی گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں۔

شری راجیش پائلٹ جی جو اس وقت اتفاق سے یہاں موجود ہیں اور ہمارے ملک کے ذمہ دار وزیر داخلہ ہیں۔ میں ان کی توجہ چاہوں گا۔

انھوں نے بار بار اعتراف کیا ہے اور آج اس ہاؤس میں بھی انھوں نے فرمایا ہے کہ ریاستی انتظام میں پوری طرح تال میل نہ ہونے کی وجہ سے یہ افسوسناک المیہ وجود میں آیا ہے۔ اس علاقہ میں اس روز خاطر خواہ ایک تعداد میں حفاظتی دستے بھی نہیں تھے۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ — میڈم وائس چیرمین صاحبہ — جہاں تک حفاظتی دستوں کا معاملہ ہے ... آدمی آئے اور جدید ہتھیاروں سے ساتھ لیس ہو کر آئے۔ مظلوم نہتے لوگوں پر گولیاں برسا کر چلے گئے۔ حکومت کہتی ہے کہ ۳۷ لوگ مارے گئے ہیں مگر حکومت

ہمیشہ مرنے والوں کی لاشوں کو چھپاکر ۔ مرنے والوں کا ڈاٹا کم پیش کرنے کی پرانی مجرم ہے۔ پرانے طور پر اس رسم کو زندہ رکھتی ہے میں کہتا ہوں کہ ۱۰۰ سے زائد لوگ مارے گئے۔ ۱۰۰ سے زیادہ لوگ گھائل جبکہ ہماری ۳۰۔ ۳۰ گاڑیاں موجود تھیں اور ان ۳۰۔ ۳۰ گاڑیوں میں ہمارے سپاہی اور قانون کے محافظ موجود تھے۔ کیا بات ہے۔ کتنے طاقتور تھے وہ۔ کتنے جدید اسلحہ جات سے لیس تھے وہ اگروادی اگروادی آکر ۱۰۰ آدمیوں کو گولیوں سے بھونتے ہوئے نکل گئے۔ اس کے بعد ہماری بہادر فوج میں نے پیچھا کیا تو صرف دو انتہاپسند مارے گئے اس طرح سے یہ ملک کی حفاظت کی جائیگی تو میں اتنا ہی کہوں گا کہ ۔

اگر یہی ناخدا رہے گا اگر یہی رہبری رہے گی
تو ہر کنارے پہ آکے کشتی اسی طرح ڈوبتی رہیگی

اس لیے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ ایسی سرکار کو بنے رہنے کا کوئی حق نہیں ہے جو مظلوم انسانوں کے تحفظ کا کام نہ کر سکے۔ ہم دنیا کو کیا منہ دکھلائیں گے۔ دنیا کے کسی ملک میں ایسا نہیں ہوتا کہ پناہ گزین اکٹھے ہوں۔ اگر پناہ گزین دو چار دس پندرہ بیس پچیس پچاس ہزار ہوں۔ انکے کھانے پینے کے انتظام میں کمی ہوئی تو یہ بات تو

شری جلال الدین انصاری "بہار": اپ سبھا ادھیکش مہودیہ۔ دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارا دیش نرسنہاروں کی لگاتار گھٹناؤں سے گرست ہوگیا ہے۔ ودیشوں میں لوگ بھارت کو اس بات سے جانتے ہیں کہ ہمارا دیش نرسنہاروں اور گھوٹالوں کا دیش ہے سوال صرف بار پیٹا کا نہیں ہے۔ آئے دن ہمارے دیش کے وبھن حصوں میں کہیں نہ کہیں اس طرح کے نرسنہار ہوا کرتے ہیں۔ میں کہنا چاہونگا اپنی طرف سے اور اپنی پارٹی بھارتیہ کمیونسٹ پارٹی کی طرف سے کہ آج ہمارا دیش جاتیہ دنگوں میں۔ نرسنہار اور

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे) ; शुक्रिया, आजमी साहब । अब डा० बी०बी० दत्ता ।

DR. B. B. DUTTA (Nominated): Madam; first of all; I would like to express my deep anguish over this carnage that took place in Assam. I fully share the sentiments expressed by Mr. Obaidullah Khan Azmi about the plight of those helpless people who have suffered. This is really something beyond description. We would only like to be assured in this House that Home Ministry at the Centre and the State Government of Assam would fully exercise themselves to the task of ensuring that such a thing does not recur. We would not like to see the repetition of what has happened. Madam; I would like to make a few observations regarding this incident; but not repeating what the other hon. Members have said; so that the problems that afflict the North-East today is better understood by this august House. We, the Members who live in the North-East, have a feeling

that we are not properly understood, that a correct perception of the problems is lacking on the part of the part of the national leaders. It is not a question of the Congress (I) or the Communist or the Janata Dal or the BJP. I think that all the political parties have to take the blame that they have not properly studied and properly understood the North-East. Now it is in this context that I would like to interpret wha has happened in Barpeta. See this not as an an isolated incident. In fact, if we study the happenings in the last fifteen years or so, we will find that this incident is not distinct from other incidents. For example, I would like to remind you of what happened in 1980 in Mandal in Tripura. There was a massacre on far larger scale. There was a clash between the tribals and the non-tribals and the non-tribals were at the receiving end. Then of course, there was counter-violence to an extent. Then you remember what happened in Nellie in 1983 in Assam and also in other parts of Assam. This was also a massacre in an area where, since a majority of them are Muslims, they become the largest victics. Then again you remember that after the Babri Masjid demolition in 1992 there was a massacre in the Naogaon area where about 100 Hindus were killed and many villages were set on fire. These are examples of an organised crime everywhere—in Tripura, in Assam everywhere in the North-East. Then you remember the Naga-Kuki clashes in Manipur. Hundreds of Nagas and Kukus died in mutual clashes. It was a very heart-rending scene of what happened in Manipur. Then, we must also remind ourselves that about 100 Muslims were killed in Imphal about two years ago.

You cannot interpret all these happenings only by blaming one Chief Minister here or another Crief Minister there or calling for the resignation of the Chief M inister or even demanding impositon of Pres dent's This region has been in turmoil since Indepdence. It started in Nagaland right in the 'fifties and then gradually the etire refion had been drawn into a vortex of conflicts. Then, gradually the autonomy movement started; the independence movement spread. Of course, the Government of India then shifted from its earlier position of having a united compasite state in that sensive area and tried to accomdate the aspirations of so many ethnic, linguistic and other groups of people there. I must also tell this House that we should not forget that when the States Reorganisation Commission reached Assam in the early fifties there it ended. The principle of formation of States on the basis of language had to be abandoned. It ended there. After that the formation of the States started not on the basis of economic viability, not on the basis of language, not on the basis of ethnicity, but o the basis of meeting the aspirations of small collection of ethnic groups so to say. That is how by expediency, as all of us know today, we had gone in forf the formation of the smaller States. The Indian Constitution has been stretched to its farthest limits to accommodate the wishes of the multifarious ethnic and linguistic groups living in the North-Eastern Region.

Now, after all this has been done, where have we come to? After nearly half a century of freedom and after about 25 years of passing the North-East Reorganisation Act of 1971, we have to ask where we have landed ourselves. What has happened? The situation in the Narth-East today is worse than before.

Now, other things have also happened. Something has gone wrong in Burma. Something has gone wrong in Bangladesh. New forces have emerged. New currents an dcross-currents have penetrated into the North-East and in the midst of there conflicting movements, say, for autonomy by smaller ethnic groups, those forces are

operating in the North-East. They are taking full advantage of the quarrels amongs us and we find that we are in a very pitiable situation. So, whenever anything happens in the North-East, for one, being an insider, can tell you that I am always apprehensive that this is not the doing of only the local people. When the Bodos are doing a massacre, you cannot believe that only the Bodos are doing it. Where are the armed Bodos staying today? They are right inside Bhutan with their arms and ammunitions. How come that Bhutan dares to accommodate the Bodo camps inside the Bhutanese territory? What is the strength of Bhutan? Where from they get this strength? They come from inside Bhutan and strike on these helpless people and then they again go back to Bhutan. You see, the Assam Chief Minister was telling that he has been making a demand on the Centre that the right to operate inside Bhutan should be given to the para-military and military forces who should also be given power to chase them to cross the borders and to demolish those camps

Now, the ULFA, people have gone to Bangladesh. They have set up so many camps. They are being trained by the ISI. You see, this is the problem. ULFA has also again entered Bhutan. Now, all this combination is very difficult to be controlled only by the Chief Minister, only by the State Government. It requires a proper understanding between the State Government and the Centre and I should say, it requires a national consensus. All political parties and their leaders have to address themselves and see how to contain the situation in the North-East, which because of partition, has created so much of rigidity in mobility in that region that it has become a herculean task to industrialise that area. All the rail, roads river and links, everything had been shapped. The result has been, that the North-Eastern region, as a resut of partition, is impoverished, Bangladesh has been impoverished. Shri B. Kalita was talking about economic backwardness. If economic cooperation between Bangladesh and North Eastern Region does not come, neither is Bangladesh going to have its economic freedom nor is the North-Eastern region going to develop as much as it should. The North Eastern Region is being maintaintained by the might of India by facility. But the economic destiny of Bangladesh is definitely involved with the destiny of the North Eastern and Eastern States of India. On this front, we are not adjusting ourselves. Now do you face the chalenges in this area? How we can go ahead? We are looking the other way. We are keeping our eyes away from the real situation.

Madam, I tell you about another phenomenon that has appeared in the North East. And I warned the officials in the Home Ministry and the Hon'ble Minister himself present in the House should pay attention to this. You see, the 'majofity' in India is not very famous for behaving well. As a result, the 'minorities' were estranged. The majority is not just, that is why 'minority' refused to adjust. This conflict between the 'majority' and the 'minority' has led to so many evils. It has happened in the North-East. Now, the group which is in minority today is trying to become the majority. In order to become the majority, it requires the ethnic slogan and it requires a territory over which it will be in a majority. Now, take the instance of the Bodo people. The moment you them autonomy. One group is wise enough, progressive enough to accept the formula that they will be under the framework

of the Assam Government, enjoy the autonomy yes, all the economic rights and everything But the other group is not happy. They want statehood and in order to bargain, they take to arms. There are many people to help them in this, as I have said. So, it goes on like this. Ultimately, what you will find is that in the Autonomous Council Area no non-Bodo will be able to live. This is the phenomenon in the North-East. Because the militant groups will gradually come inside the autonomous area. They are the heroes who had killed so many people, who did the ethnic cleansing who had earned a name. They will win elections. They will influence the politics in the Bodoland area and they will make the lives of the non-Bodos miserable. This is the phenomenon that is visible in the North East. Small ethnic groups are becoming the majority in one area and even more aggressive than the large majority group. They is a difference between large majorities and small majorities. Small majorities in order to retain their majority status and to ensure that never in future nobody should be able to become majority, even projecting this fear, this imagination into the minds of the people, in the psyche of the masses, the slogan goes on and this is a new phenomenon. It should be studied. We have got a lot of problems because nowhere in India you have had such small States. Even our Chief Ministers, administrators and officers are finding a lot of difficulties because these difficulties are cropping up from the smallness of the size of the state smallness of the constituency a situation what they discribe as localism, and this creates sometimes a law and order problems. And once the law and order problems are created then they spread in all directions given the fact that many hostile agencies are active in the North Eastern Region. That is why I say that the North-East should not be studied just in a stereo-tyned manner. There must be a serious study about the problems, the nature of the problems. The problems should be categorised, and for each category of problems, we have to find out what should be the ideal response. You cannot apply a blanket response, as you are doing in other States. This is very wrong. This is not the way to solve the problem. Take the case of Assam. There has been always a problem in Assam that Assam does not have a correct leadership to assimilate all the people together, to keep them all together. When Hiteswar Saikia was the Chief Minister, in 1985, he had to go because the Congress sacrificed and came to terms with the AASU movement, and the election was called and a majority Government was dismantled, and after the election, the AGP came to power. Nice. The Congress sacrificed for the larger national cause saying, let the people be happy. But what happened? Ultimately, a terrible situation prevailed in Assam. Again the Congress was called back by the electorate. Again Mr. Hiteswar Saikia and his party were elected back to power. Do you know that there was no canvessing, there was no campaigning? People were so much fed up during the AGP rule that they voted spontaneously. There were no election meetings in the constituncies. There were large queues on the day of elections when people spontaneously voted. I had never seen in my life any such voting. Today, Mr. Hiteswar Saikia is in his third year; he has completed three years in power. He is the man who has said, "I give economic rights, all kinds of rights to all groups of people". He has declared the other day in Shillong in a conference, "I will give for every ethnic group, for everybody as much autonomy as is possible to give to anybody." So, here is a Chief Minister who has tried to accommodate the wishes of all groups of people to keep we have seen what has happened elsewhere Everything has gone wrong. And, therefore, no such experiment can be made. It is not realstic. So,

he is going ahead with this. Now, take the Muslims. There is a group of Muslims which is blaming Mr. Hiteswar Saikia that he has masterminded this carnage. What an irony to say this about a man who is being blamed by a lot of people that he is pro-Muslim, a man who has been fighting for the Muslim's rights, a man who has fought tooth and nail for the inclusion of Muslims in the electoral rolls of Assam? What an unkind thing? Wherever and whenever anybody does good thing, we must be fair enough to say that he has done the right thing. But this is not the way to behave, this is not the way to asses the leadership. The role of the leadership in any State, in any country is crucial. You cannot deliver anything through any party if the leadership is not correct. Hiterswar Saikia is the man of the hour. He should not be disturbed. He should receive stemgth from all of us, from all political parties in order to meet the situation. This is my appeal to the Members of the House to appreciate what is happening in Assam, and my appeal to all members that he be given a big hand.

Madam, I would like to draw the attention of the House to one important thing. Whenever anything in the North-East is being discussed, naturally the question of infiltration comes. Shri Vishnu Kant Shastri has brought the question of infiltration. There are other speakers in the other House and here who have brought this. Well, on that, I have got a submission. Mr. Hiteswar Saikia has taken a stand, "I am the Chief Minister of Assam and I am guided by the official documents. I have got a census report to go by. And whatever is given in the census report, on the basis of that, I get my civil supplies quota from Delhi. I am using every time the census statistics. And how can I say there is infiltration when the census does not give me any indication?" This is the official stand that he has taken. He has not said anything beyond this. Now, we, those who are living in the North-East, have also studied the problem. We can be very frank and fair. We can tell you that the problem of infiltration—the words is not a very happy word for some reasons—the problem of migration of people from Bangladesh into India—we do not know how many people have entered which State in what strength—is very much there. It is a problem about which the Home Ministry, External Affairs Ministry in Delhi should address themselves to understand this problem. I ask one question: If at the time of partition, there was only 37 per cent in the area called East Pakistan and now Bangladesh, then how come that today the percentage of the minority population in Bangladesh is only 10.5? Where have these people gone? Have they gone to Burma? Have they gone to China? Have they gone to Nepal or to any other neighbouring country? No. Where have they gone? They have come here. I was in Bangladesh. I was in East Pakistan. I was born there. Some people are still there. I came to India. I know how many people came from my village. There is only one family remaining there in the village where I was born. People have come over here. Many people have come.

Subsequently,, to tackle this problem, we took a stand. We said that after 1971, after the liberation of Bangladesh, there was no reason for anybody to come. This is the cut-off year and this is being maintained. Before 1971, whatever had happened had happened. We should not call those people as foreign nationals. We should not call anybody as a foreign national just on mere suspicion. We must prove that he is a foreign national. We should not harass anybody

in the name of foreign national. If somebody is harassed just because he is a Bengali-speaking person, if you say that he is a Bangladeshi, it is very unfair. Today, something goes wrong in Barpeta and you say that it is becuse of the Bangladeshis. This is wrong. If you do not prove that some body inside the camp was a Bangladeshi, you shoud never say that. There is no right for anybody to speak from the so-called moral plank that they are Banglodeshis and that, therefore, they deserve this kind of treatment. This is very unfair. Somebody, some Member, hinted at such a thing. This is very unkind. We cannot do this. We are a civilised people. We are living in a civilised society. We are a democracy. We cannot behave like this. If somebody turns out to be a Bangladeshi, there are procedures laid down for dealing with him.

Madam, I would submit here that there are certain factors which sould be kept in mind. The Home Minister is not here. I do not know why. But the Minister of State for External Affairs, Mr. Bhatia, is here. I want to draw his attention. You should get ready now. More people fuom Bangladesh are going to cross the border and come over to India. I say this because now, in Bangladesh, the Government has started a survey of the minorities' property. Why is this survey being conducted? Their motive is to take over all the enemy property. As the property was in East Pakistan, it is called enemy property. Now, the Bangladesh Government wants to distribute this property among the majority population. This has created a panic among the minority population of Bangladesh. Many intellectuals, many progressive Muslim intellectuals, in Bangladesh have written about it and they have protested against it. But I do not know why we are keeping quier. Mr. Bhatia is here. I would like to ask him. Why are you keeping quiet.

Madam, this is a very serious problem. The root cause is there in Bangladesh because of which we are the victims. Any large and quick demographic change taking place anywhere in the world would create social tensions. It has created tensions ir the North-East. We cannot deny it Therefore, you have to be careful If something happens in Bangladesh because of which we, in India, suffer, we have got every right to take up the matter with the Bangladesh Governmnt and ask them as to what they are doing. Is India an enemy country? Why should the Enemy Property Act be retained in Bangladesh under the changed nomenclature of Vested Property Act? Bangladesh is not a successor Government that it is bound to abide by all the rules and regulations of the earlier Government. It is a Government which came into being by a revolution. It is a Government which came into being with the help of the Indian Government and the Indian people. Then, how could they retain this Act? Why has the External Affairs Ministry allowed Bangladesh to retain this Act because of which many peple have been killed their property snatched away? The Governmnt has to answer this question. You have to do something right now. I got reports only three days back. Peopde coming faom Bangladesh have told me.

There is another important thing which I would like to point out here. Bangladesh is now an ideal canvas for religious fanaticism. There is galling poverty there. There is no development. There is no industrialisation. There is no infrastructure which can cause growth. On the top of it, there is a population explosion. The absence of these growth factors provides an ideal canvass for religious fundamentalism. This is where the I.S.I. comes into

the picture. Fundamentalist groups have appeared in strength in Bangladesh. They are gradually inching forward to capture the entire political apparatus in Banglodesh. If Bangladesh goes the fundamentalist way, I can tell you that you are in for a serious battle along the North-Eastern border. You do not know what is going to happen there. In fact, it would be worse than Kashmir. Therefore, wou should act right now.

Madam, we are friendly with Bangladesh. They are a very nice people. They speak the same language as I do. There is no difference between myself and a Bangladeshi except that he says 'Allah' and I say 'Bhagwan'. There is no difference between us. Our destinies are the same. Our culture is the same. We should move towards unity. Elsewhere in the world, many unity movements are taking shape. Why should we not learn a lesson from the other people? Why should we not come closer? Our economic planning should be the same. Take, for example Malaysia. See what a beautiful arrangement this Muslim country has made. They have accommodated their every group so nicely. The economic right of every group has been guaranteed. Why should you go far out to seek bad examples? That is why I say that the Ministry of External Affairs and the Home Ministry should give full attention to the North-Eastern areas. What is happening in Assam? What is happening in Bangladesh? What are the causes originating from those areas, because of which we are suffering here? Those causes must be attacked at the roots, not after they flower here. After they menifest here, we have an uphill task.

The other day, the Burmese army drove away the Muslims from Burma. There was ethnic cleansing in parts of Burma. The Muslim went to Bangladesh. The Bangladeshis, in turn, expelled the Buddhist from Bangladesh, and they came to India. What a marvellous thing! A British correspondent was telling me, "It is a marvellous thing going on!" And we sit quiet. After they came to India, we have a lot of problems. What to do with them? We should not fight shy of fighting this problem. We sould talk face to face with Bangladesh for their good and for our good. We should talk directly and boldly about what should be done and how we can go ahead. If this is not done, nothing will happen, I am telling you.

Why are the Muslim coming here from Bangladesh? It is because of the land hunger in Bangladesh today. The lands of the Hindus and other minorities are being taken away. Even the property consecrated to god is not safe. This is happening. We are getting the reports. I have got a list of people. I can produce it before this House. So much lawlessness is going on in Bangladesh because of all these factors and because of the operation of the fundamentalist groups. The majority of the Muslims in Bangladesh are not hostile. They are very nice people. But the fundamentalists are operating in a method, with a purpose and with a motive. You find that in no Hindu family a girl above the age of 13 or 14 is safe. You may go to Dhaka and say that you have had good friendship talks and meetings. You notice nothing. Go into the interior of Bangladesh. Everybody is sending his daughter to India. Everybody is sending his son to India. There are no economic opportunities for the minorities. They are not able to live is dignity. They are no able to protect their women or their property. They are not able to live in dignity. They are not able to protect their women or their property. They are not getting any economic opportunity.

India has got a role to play. If India had a role to play in the emancipation of Bangladesh then today India has a role to play in the reconstruction of Bangladesh in line with India. So, the Centre has to do this. It is useless to blame only the State Chief Minister and to talk of President's rule and changing of the Chief Minister. This is all nonsense; I am telling you. We have got the best Chief Minister in Assam. Assam has not yetbeen able to produce a better Chief Minister than Mr. Hiteshwar Saikia. I think we should all give a hand to him so that the things go well.

I would like to say only one thing to Pilotji. The Home Minister is also sitting here. The officers who are found guilty; those who could have avoided this earnage should be punished. If they had the intelligence report why did they not pass it on? This should be enquired into and action should be taken against them. The North-East is a place where no action is taken against culprits. If somebody commits a murder today, it is known that no action is taken against him. There are even cases where a murderer has made a confession before the First Class Magistrate. Five years later, he is a politician an MLA and then he is a Minister. This kind of thing should be stopped.

Madam with these few words, I would only make this appeal to the House. It is a very right thing. For the first time, my heart is elated that Indan Parliament has discussed the North-East. In the Lok Sabha, it has been discussed for more than five or six hours. Here also it is going to be discussed. I hope we will continue to study the problems of the North-East.

I would request you to set up, if possible, some mechanism by which you can make a fresh assessment of what is going on in the North-East in the light of all the details that have been given so far.

Thank you so much.

SHRI TARA CHARAN MAJUMDAR (Assam): Madam Vice-Chairman, I thank you for giving me this chance to speak on the subject we are discussing.

The most dastardly attack carried out by suspected Bodo extremists in the relief camp in the Barpeta District, where uprooted people of the religious minority had taken shelter after being driven from their homes which were burnt down by miscreants has left a shock wave in the State. This incident happened at Basbari, a place only 15 km. away from Barpeta where the Chief Minister; with a posse of 25 Ministers, was camping, being surrounded and guarded by Black Cats and dozens of other security men. It is strange that although there was tension all over the area since the 19th, of July and here were large-scale burning of houses and movement of people to safer places; there was no preventive action taken by the Administration to stop the gruesome incident in the relief camp. There was total failure of inteligence and criminal negligence on the part of the Administration; measures of which were busy looking after the comforts and security of the Chief Minister and his entourage of 25 Ministers. Ethnic violence spread like wild fire to several villages during the three days previous to the massacre at Bansbari camp; where about 2,000 people were takng shelter. As per reports in the papers about 60 persons, men, women and childden were mowed down and hundreds were injured More than 50,000 people have already taken shelter in relief camps, camps. The total number of persons killed and injured is yet to be determined. There is an apprehension

that retaliatory violence would spraed to adjoining districts if drastic preventive measures are not taken by the Administration. The incident has been widely condemned by all political parties and students and youth organisation who have laid the blame on the Administration. The All-Assam Students Union has given a call for "Assam Bandh" on 27.7.1994, i..e. today. In view of the Government's carelessness and lack of initiattive to tackle the situation and that their criminal negligence in meeting the situation and protecting the life and property of he people, they have lost all moral claim to continue in office and they should step down. The house of Mr. David Ledger, an hon. Member of this house and his relatives were subjected to vandalism and looting. People are complaining that Shri Shamsul Haque, a member of the Saikia Cabinet was found inciting people for arson and looting.

The Government should immediately set up a judicial commission to find out the causes of this ethnic violence and assess the adequacy or otherwise of Government action and also find out the part played by the persons in the riot and arrange to bring to book all persons found involved in the ethnic violence.

The whole trouble with the Central and State Government is that they will execute accords and thereafter go slow with their implementation. The Bodo Accord was executed without demarcating its boundaries. BAC was constituted without such boundary and in the midst of inaction; indecision and without demarcation of boundaries. As a result there has been apprehension in the minds of the non-Bodos that their rights would not be protected. Instead of sincerely trying to implement the Accord the State Government has created division in the Bodo leadership which has made its implementation more complicated.

There will be repetition of shocking incidents; if he Accord is not implemented with the sincerely and seriousness it deserves. Employment of the Army and para-military forces is not going to improve matters. The foreign nationals issue which the Assam Accord aimed at solving; remains unsolved. The forieign nationals problem; if not solved to the satisfaction of the people of Assam; will invite more serious and massive movement not only in Assam but also in the entire North-Eastern Region States have as already come together and is going to build up a massive movement in the entire region. The problem should be tackled with all the seriousness and urgency it deserves. All ideas of tackling the problem with the help of security forces and para-military fodces are to be qs hewed. Have open and heart-to-heart talks with all sections of the people including the extremists. Assure them that exploitative approach will be replaced by a welfare approached in the region and thatthe people will have control and share in the benefits from the natural resources which abound in the region.

Madam Vice-Chairman. I thank you for giving me this opportunity to participate in the discussion. I offer my condolences to the people who have last their lives and suffered in the dastardly act. We hope and pray that the Government will come forward to assude us that repetition of such things will not happen. With these words; I conclude.

SHRI W. KULABIDHU SINGH (Manipur): Madam Vice-Chairman; I thank you very much for giving me this opportunity. I will not repeat the points and answer the points which have been made by the previous speakers; particularly; by my revered friend; Mr. Dutta. He had expressed his sentiments on the crucial problems and economic problems

of the North-East vis-a-vis Bangladesh. I subscribe to the views expressed by him regarding the problems of the North-East; except one salient point regarding his praising of Mr. Hiteswar Saikia; the hon. Chief Minister of Assam. Otherwise, the points raised by him are very lucid and factually correct.

It is surprising that around 23rd July midnight more than 50 refugees were massacred and more than a hundred persons were injured in the firing. In parts of Manipur, in Senapati district in Chandel district and other parts of the Norh-East these things do take place intermittently. It is not surprising to the people of the North-East but it may be surprising to the hon. Members of this august House.

The hon. Home Minister, Shri Chavanji had called a meeting of all the Chief Ministers of the North-Eastern Region on the 19th July, 1994; and within less than six days that massacre took place in Bansbari relief camp which is in Barpeta distrist of Assam. Before this incident took place, 23 persons were killed in the ethnic strife between different communities, Bodos and non-Bodos. Within less than six days of the hon. Home Minister's announcement that the Chief Ministers of the North-East Region will raise their commandos and take suitable security measures, this massacre took place on the night of 23rd July. Immediately curfew was imposed and shoot-at-sightt orders were issued. The sequence of events which took place between the 19th July, 1994 and the 24th July, 1994 has got a certain significance because the type of weapons used were very, very sophisticated automatic weapons. The Bodo militants use remotic control divics also.

4.00 PM

What is its significance? We have read reports in the national Press that all sorts of militants are getting traming on the soil of Banglades. They are getting training from the ISI as Well as the Bangladeshi Institute of Strategic Studies. The neighbouring countries have intelligence on us. The ISI and the Bangladeshi Institute of Strategic Studies are giving training to the militants of the North-East including the Bodos, on the soil of Bangladesh. My friend, Dr. B. B. Dutta, was asking for the upliftment of the North-East along with Bangladesh. It is a very nice suggestion. If India happens to be a country like America, we can afford to provide for the development of Bangladesh also. But India is not in that position. It is a very nice wish. But the Government of India may not be able to afford it. We do wish that Bangladesh should develop economically as well as industrially. But the Government of India cannot claim to take up that issue directly even though some financial assistance may be provided for.

Now, coming to the Bodo Accord, the creation of the Bodo Autonomous Council is very much appreciated. The culture, art and tradition of the Bodo people and their ethnic identity should be preserved. They should be encouraged. That is very right. But there are some ambiguities in the Bodo Accord. When those ambiguities were to be cleared, Shri Hiteshwar Saikia took a different stand. The leadership issue among the Bodo militants...

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): My request to you Mr. Singh will be, try to be brief. Many Members have to speak.

SHRI W. KULABIDHU SINGH: My party's time is...

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): Your party has 17 minutes.

SHRI W. KULABIDHU SINGH: I will take two minutes more. Mr. Prem Singh Brahma and Mr. S. K. Bwismutiary are the two leaders; one is moderate and the other militant. I do not know why Mr. Hiteshwar Saikia chose the militant group of Mr. Prem Singh Brahma for the Chief Executive of Interim Bodoland Executive Council. We wish Mr. Hiteshwar Saikia, the hon. Chief Minister of Assam, was a mediator and arbitrator rather than siding with one of them. If, at all why he should be siding with the militant one? That is a fatal mistake committeed by the hon. Chief Minister of Assam.

I have submitted that I take exception to the stand of the hon. Chief Minister of Assam. All the political parties of Assam, except the ruling Congress (I), have demanded the resignation of Mr. Hiteshwar Saikia and the imposition of President's rule. About the imposition of President's rule, I do not encourage it. But the removal of Mr. Hiteshwar Saikia is a must. Instead of being a mediator, he pursued the divide-and-rule policy, just like an ex-Chief Minister of Manipur—whom I would not name—who was playing the divide-and-rule game among the PLA militant groups in the State of Manipur. One faction of the PLA was supported by the ex-Chief Minister against another faction. Ultimately, the other faction also wanted to create more trouble. When a Chief Minister wants to side with a group of militants, it will create havoc in the long term. The Assam Chief Minister siding with a faction of the Bodo militants is not appreciated and he should go.

With these few words, Madam, I conclude.

SHRI G. G. SWELL (Meghalaya): Thank you, Madam Vice-Chairman. knowing the constraint of time, I will take only three or four minutes and thank you, Madam Vice-Chairman. Knowing the constraint of time, I will take only three-four minutes and I will put certain questions to the Minister of State for Home Affairs. I will request Mr. Ahluwalia not to disturb me. I am going to take only three-four minutes. I would like to put certain questions to the Minister and I will expect him to provide answers to those questions in his reply. Firstly, I would like to congratulate the Minister for his moral courage, for his anguish and for his concern. Mr. Minister, you went to Assam where these things took place, where the massacre took place and you have reported to the Press that you excoriated the Government of Assam for inaction, for indifference, for inefficiency and for absense of interest. You may correct me if I am wrong. But you have not contradicted those report and in your speech in Lok Sabha, you also had admitted that there were certain lapses. I appreciate this kind of approach to the problems. Now, what I would like to know is this. Soon after the explosion by a remote control device on the police vehicle that killed a police officer and a number of policemen was it a fact that a certain Minister of the Government of Assam led a group of masked men and attacked a Bodo willage and the maior atrocity took place? (Interruptions) I am putting a question to the Minister. He led a group of masked men, attacked a Bodo village, committed atrocities on Bodo women and what happened after that, was a retaliation by the Bodo security force. I would like to know whether this is correct or not. Secondly, is it a fact that the same Minister barged into a police station in this area and openly encouraged a certain community to retaliatory action. This is what has been stated in the paper. The name has been mentioned—a certain Minister, Shamshul Haque. I would like to know what the back ground. Haque is Where is he

now? If this is really the trouble, if this is what he has done, then he was responsible for the entire incident in Barpeta. Where is he now. Has the Chief Minister of Assam taken any action against him? This is the second question.

The third question I would like to ask is whether today, there is an "All-Assam bandh" called by the All-Assam Students Union as a protest against the maladministration of the Assam Government. Is this a sign that the problem is widening and escalating.

The fourth question is whether you apprehend that some kind of a thing would heppea in other parts of Assam such as Naogaon, where after the demolition of the Babri Masjid, the Muslims had massacred a large number of Hindus and what precautions are you taking?

And the last question is whether it is true that the international narcotic cartels are now having nexus with the drug lords in the Golden Triangle Khunsa and that the entire drug from that area is passing through Assam into the rest of India and into the rest of the world. I would like to know whether it is true that the official dignitaries are involved in the drug traffic and whether it is true that the Customs Department have advised. certain police check posts certain VIP movements And a particular piece of information was given that the movement of a particular VIP should be checked because he was suspected of carrying drugs. Is it true that he came with the red lights blazing away and with a lot of armed police behind him on the truck, and rushed through the police check-post? Now you are very well aware, Mr. Minister, that drug and terrorism go together, narco--terrorissm where a lot of drug-running is there. There is a lot of money. There are a lot of weapons. How are you going. to control the situation? I would like the replies to these Barpeta questions to be pinpointed. I would also like you to see whether you have a plan for the entire area because today Assam and the whole of the North-East is a kind of a devil's brew.

Thank you, Madam.

SHRI DAVID LEDGER (Assam): Madam Vice-Chairperson the happenings at Barpeta are, indeed, unfortunate, to say the least. The burning of villages, the looting of properties, the loss of lives, the plight of 50,000 homeless people, have made each one of us sad and have left us wondering as to what has suddenly happened, as to what has suddenly gone wrong. Madam, our sympathies go with the innocent people belonging to both the communities who have had to bear the burnt of these attacks. Madam, the brutal massacre at Bansbari relief camp which left 40 innocent people dead and scores severely injured on Saturday, the 23rd July deserves to be condemned in the strongest possible terms. These acts were not only criminal but also inhuman. There should be no effort spared to apprehend the culprits, the perpetrators of these heinous crimes.

Madam, it pains me to say that I am personally one of the victims of the happenings at Barpet a district. On the night of 20th July some miscreants broke open my home in my absence. My family and myself were all in Delhi. I had come here for this session. They broke into my house, they looted the properties, they damaged the properties. They broke open my uncle's house which is adjacent to mine. They had a tip-off during the day. They ran away for their life. The whole house was ransacked. The properties were looted. Madam, this is what happened. This has happened to a Member of aPrliament. I would not have raised it otherwise, but I am raising this only to bring the attentoon of the hon. Members to the

(Shri David Ledger)

seriousness of the problem. In the normal course, Madam, had I not been in the Parliament, perhaps I would have ended up in one of the relief camps and perhaps. Pilotji and Saikiaji would have had to give me relief material and Rs. 50,000/- for building a house. Fortunately, I am a Member of Parliament. I am here, I am in a position to narrate these things to you.

Madam, when my friends from the other side were speaking, I was listening to them very carefully. A lot of accusations have been made against the Chief Minister, Mr. Hiteshwar Saikia. A lot of allegations have been brought against him. Some hon. Members have demanded his resignation, some have demanded his dismissal, others have demanded the suspension of the Assembly. All kinds of allegations, wild allegations have been brought, but, Madam, by accusing the Chief Minister, by blaming the State Government one cannot solve any problem. Madam, let us undrestand that we have a problem and the problem is very, very acute. Madam, the enormity of the problem can be best understood by the fact that the Chief Minister himself, along with his Ministerial colleagues and senior police officials were camping at the site for almost a week. It only shows that he was concerned. It shows that he was serious about it, he was not sitting idle. I personally accompanied him to the affected areas on the 22nd of July. We went to the camp, we talked to the people, we oversaw the relief operation, the relief work. He was giving instructions. The officials were with him. The Army officials were with him. So, it is not correct to blame the Chief Minister because it does not lead us anywhere.

Madam, it is being stated that he has not done anything. The Chief Minister, the State Government, had submitted a plan to the Central Government to seal all the 21 routes in the Bhutan border one year ago. These routes are used by the Bodo Scurity Force for their movement. This report was supmitted after consultation with the Ministry of Home Affairs. He has also given a requision—our hon. Minister of State for Home Affairs is present here; he will agree with me—for 15 additional companies of paramilitary forces. Mr. Pilot has made a statement the day before yesterday in the Lok Sabha that he has already directed that 5 companies of paramilitary forces should be released and should be kept at the disposal of the District Administration. We would like to put on record our appreciation for what Mr. Rajesh Pilot has done. He has acted promptly without losing any time. He went to Barpeta on the 24th of July, on receiving the information of Bansbari massacre, along with two Ministers, Mr. P. M. Sayeed and Mr. Tarun Gogoi, and some of the M.Ps. from Assam. He held discussions with the State Government, with the Army officials, with the police officials and with prominent citizens. He promised all possible help. I would like to put on record that his visit has eased the tension a lot and infused a lot of confidence in the people there. I would only appeal to him to make available more paramilitary forces so that the State Government can have a helping hand.

Madam, those of us who are gunning for the Chief Minister those of us who are running after the blood of the Chief Minister, would do well to, first of all, realise the enormity of the problem. The penchant for scoring debating points is not going to help us at all. We must rise above petty party considerations, put our heads together and see how best we can solve this problem. The Saikia Government is a duly elected Government. It is a democratically elected Government. So, there cannot be any question of dismissing it. The

problem will have to be solved by the State Government with the help of the Centre and with our co-operation. The Congrss has been blamed for a lot of things. There are efforts to crucify the Government whenever there is a problem. Those of us who are trying to be very righteous today, those of us who are trying to crucify the Congress would do well to remember that the Congress was not the only party which ruled Assam from 1947 to 1994. We had the Government of the Janata Party from 1977 to 1979 for a period 28 months. We had an AGP Government which ruled Assam for 4 years and 11 months from 24th December, 1985 till 27th of November, 1990 when it was dismissed. I don't remember any action which these Governments had taken on these fronts. I was in the AGP. There was no political will to solve the minority problem. There was no political will to solve the tribal problem. Some of us had to leave the AGP in utter disgust. We should appreciate the efforts made by the Congress Government. At least, political will has been disployed by it. Efforts are being made. The Bodoland Autonomous Council has been established. An effort has been made to solve the tribal problem. An effoft has been made to salve the minority problem. It is for the first time that in the history of Assam land pattas have been given to the minorities in the riverina areas. Yet the Congress has been crucified and yet the Congress has been blamed. There are the facts which I have stated and these fact cannot be wjshed even if anybody wanted.

Madam, when we venture to participate in a discussion on a subject as sensitive as this we should have an insight into the genesis of the problem. May I say that the tribal problem in Assam is basically a land problem? In 1949, when Gopinath Bordoloi was the Chief Minister of Assam, 37 tribal belts and blocks were created in accordance with the provisions of Chapter X of the Assam Land Revenue Regulations, 1886. The criterion was that each belt and bloc would consist of, at least, 51 per cent of tribal population. In the course of time, encroachment into vast tracts within these belts and blocks took place. This encroachment was made by the people, plains people people from within the State, non-tribal people from within the State as well as immigrants from the erstwhile East Pakistan and today's Bangladesh. The Bodo people, gradually, became outnumbered in these belts and blocks. Having lost their lands, they became apprehensive of loosing their identity. Gradualy the apprehension and fear took the form of agitation. There were peaceful agitations. There were violent agitations. We have all heard about that. Trains were blasted and bridges were blown up. There were bomb blosts in the heart of Guwathati city in Paltan Bazar There was a bomb blast in Dispur which is the State Capital. A lot of innocent people died. After the prolonged agitation, and as a result, as a culmination of the goodwill of the Central Government and the State Government headed by Shri Saikia, the Bodoland Autonomous Council was formed in February, 1993 comprising 2,500 villages on the North Bank of the Brahmaputra. I do not say that the Bodoland Autonomous Council has fuly solved the Bodo problems in Assam. But an effort has been made. There are still controversies. There are still groups which are not satisfied. After the latest round of discussions in Delhi, 250 more villages have been added. Still there are demands, I would like to urge upon the Government that all these groups, the All Bodo Students Union, one faction of the BLP which is not satisfied with the Accord and also the Bodo Security Force—I would like to draw the pointed attention of the hon. Home

(Shri David Ledger)

Minister—should be taken into confidence. Their views should also be taken into account.

I have given the background, the genesis of the problem. Let nobody misconstrue me. Let nobody misunderstand me. I am not trying to justify anything. I am not trying to justify what has happened there. What has happened there deserves to be condemned in strongest possible terms. But, when I mention these things, my only intention is, my only appeal is, that when we think about the problem, when we try to deal with the problem, we should deal with it in its totality, in its correct historical perspective, in its correct historical background.

Let us not try to find solutions in a hurried manner. Let us not try to find solutions in a piecemeal manner. The Barbeta situation is not an isolated incident. It is the external manifestation of a much bigger problem. Prior to Barbeta we had the Kokhrajahar incident on the 27th May, 1994 and prior to that there was the Bongaigaon incident in October, 1993. There is going to be more of what has happened unless we take a serious note of the situation. We must also be aware of the evil designs of the rumour-mongers.

The Vice-Chairman (Shri Satish Agarwal in the Chair

I would like to draw the attention of the hon. Minister who is present here to one example. Shri Prem Singh Brahma, who is the Chief of the Bodoland Autonomous Council, visited the affected area on the 21st of July. So, I also went there after receiving the information. But, his intention was good which cannot be doubted, which cannot be questioned. He went there to take stock of the situation. But, a section of the rumour-mongers got a news, which was printed in the newspapers, that it was Mr. Prm Singh Brahma who had incited the Bodos against the minorities and it was all because of him that this has sappened. I find it thoroughly ridiculous because Mr. Prem Singh Brahma is a moderate leader. The responsibility of the Council has been left on his shoulders and he has always been opposed to the Bodo Security Force. Yet, these are the allegations. We have to be very careful about this rumour-mongering. And these rumours have been written in the newspapers. I dare say that some of the newspapers have behaved in a most irresponsible manner. This is most unfortunate. This is not the time to indulge in sensationalism. The newspapers have a responsibility towards the society, especially, at the time of a crisis of this magnitude. They have to be very cautions in publishing their news. Sir, I was just trying to suggest that a dialogue with the BSF is essential. Sir, there may be arguments contrary to what I say because the BSF is a banned outfit today. The Government of India has had dialogue with banned outfits umpteen times. The ULFA was a banned outfit. There was a dialogue with them. Today, except a very few, they have come overground. Almost 4,000 ULFA members have surrendered and they have joined the mainstream. My feeling is that if there is a sincere effort to bring them round to the negotiating table, it will yield results. There may be a precondition. We can tell them, "You should cease all violent activities; otherwise, we will not talk to you." There can be a precondition. There have been such preconditions in the past. I would like to appeal to the Government of India that the BSF should not be underestimated. They are strong; they are well-equipped; they are well-motivated. I come from that area and I know it. They have a very safe sanctuary in Bhutan the ULFA did

not have. They have it now. It is not possible for our forces to go in pursuit of them in Bhutan unless we do something at the diplomatic level with the King of Bhutan. The BSF is strong-armed, more than the ULFA or any other outfits in Assam. I am saying this from experience. I am saying this with all responsibility. A large number of All Bodo Students Union leaders, who did not surrender, have joined the BSF with their arms and the BSF ranks have swelled. Sir, the Government of India has to take it seriously. Over and above the army operations, the operations of the paramilitary forces have to continue. There can be no stopping of these operations. But, at the same time, the effort for opening a channel, for opening a dialogue, should also be there. My second suggestion is, I am in full agreement with my hon. friends here, drastic steps are to be taken to contain this situation, to apprehend the culprits and to flush them out of the area. But, at the same time, utmost care should be taken to ensure that the innocent Bodos are not harassed in any way. Sir, if the innocent Bodos are harassed, that will only drive them in to the fold of the BSF and this is exactly what the BSF wants. They want that the common man should be brought into their fold. We should not play into their hands. We should try to isolate them. The strategy should be to isolate the militants and to get the full support of the common man Before I conclude, I would just like to say one thing. The Bodoland Autonomous Council was created in order to fulfil the wishes and aspirations of the Bodo people of Assam. Sir, one of the preconditions was that the interest of the non-Bodos the non-tirbals, would be secured. This has to be ensured. The minorities have to be protected. The minorities living within the BAC area, outside the BAC area or anywhere in the country, have to be protected because this is our Constitutional obligation. In like manner, the tribals who are living outside the Bodoland Autonomous Council area also have to be protected and their interests also should be secured. All the Bodos should not be looked down upon as villains, as all the Muslims should not be looked down upon as Bangladshis, as Dr. Dutta has rightly said. This is a wrong perception. We should be more balanced in our approach. We should be more pragmatic in our effort. Hopefully, we will be able to create an atmosphere where Bodos and non-Bodos, Hindus, Muslims and Christians like me, tribals and non-tribals, will be able to live, once again, in peace, mutual trust and in a sense of brotherhood. Sir, before I conclude, I want to make one appeal to the Members on the other side. Let us not try to politicise this issue. What has happened in Barpeta, what has happened in Assam is only the tip of the iceberg. What has happened there today might happen tomorrow in any other part of the country. It might snow-ball into a major problem which would engulf more parts of the country.

[Shri David ledger]

Sir, attempts have been made to denigrate one individual. Attempts have been made to criticise the Chief Minister, a man who has been able to restore peace and normalcy in a State which was ridden with strife and violence. We should go back and think about 1991. And what is the situation today in 1994? He has been able to transform the whole situation, the whole scenario. Peace has been restored. Normalcy has been restored. This is one incident which has happened—we have to admit it—due to the failure of the administration which the Home Minister has been candid enough to admit. And we also admit it. It was the failure of the district administration. The DC and the SP have already been transferred. Now more efficient people have been posted in Barpeta. This is the latest development. Only today I was finding out the facts, the latest position. So, let us not try to blame somebody and sidetrack the whole issue. We all have to come together into this, we all have to join hands and we all have to put our heads together. Let us not politicise the issue, and let us try to have a dispassionate approach towards this whole problem. As I said, today it is Assam, tomorrow it might be any other part of this country. Thank you, Sir.

उपसभाध्यक्ष (श्री सतीश अग्रवाल) : समय का ध्यान रखिये अंसारी जी ।

श्री जलालुद्दीन अंसारी (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज हमारा देश नरसंहारों की लगातार घटनाओं से ग्रसित हो गया है । विदेशों में लोग भारत को इस बात से जानते हैं कि हमारा देश नर सहारों और घोटालों का देश है । सवाल सिर्फ बारपेटा का नहीं है । आये दिन हमारे देश के विभिन्न हिस्सों में कहीं न कहीं इस तरह के नरसंहार हुआ करते हैं । मैं कहना चाहूगा कि अपनी ओर से और अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि हमारा देश जातीय दगों में, सांप्रदायिक दगों में, नरसंहार और घोटालों में धू-धू कर जल रहा है । लेकिन दुख की बात है कि इन समस्याओं के सही समाधान के लिये जो एक राष्ट्रीय समझदारी होनी चाहिये, जो एक देशभक्ति का तकाजा होना चाहिये वह न हो करके हम दलगत भावनाओं में आकर, दलगत राजनीतिक लाभ के लिये इन समस्याओं को सही समय पर हल करने के बजाय इसको बढ़ाया करते हैं । मैं कहना चाहता हूं कि यह जो घटना है इसकी जितनी भी निंदा की जाय वह कम होगी । यह शर्मनाक घटना है । जब 13 जुलाई को बारपेटा के इलाकों में जातीय तनाव, सांप्रदायिक तनाव और झगड़े शुरू हो गये थे तो वहां की सरकार और केन्द्रीय सरकार क्या कर रही थी ? अभी हमारे मित्रों ने कहा कि मुख्य मंत्री पर अटैक करने की जरूरत नहीं है । मैं मुख्य मंत्री को यह नहीं कह रहा हूं कि वह गलत है । उनके मुख्य मंत्री बहुत अच्छे हैं और अच्छे होने भी चाहियें । लेकिन 13 तारीख को उस क्षेत्र में जिस बात की शुरूआत हुई उसको रोकने के लिये उन्होंने कौन से कदम उठाये ? बसमरी के शरणार्थी कैंप पर गोलीबारी करके 60—70 लोगों को मारा गया । क्या यह कोई नई घटना है ? मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि भागलपुर दंगे के समय 125 आदमियों को परिवार के साथ एक स्कूल में लाकर रखा गया और फिर पुलिस संरक्षण में रखा गया । पुलिस के संरक्षण में रहे और पुलिस के सरक्षण में दंगाइयों ने हमला किया । पुलिस चुप रही और 125 आदमियों का कत्लेआम हुआ । क्या यह भारत सरकार

को मालूम है ? जब इस तरह की घटनायें पिछले दिनों घटित होती रही है तो फिर शरणार्थियों के कैंपों पर भी हमले हो सकते थे और हुए बचाव के लिये पुलिस का सहारा क्यों नहीं लिया गया ? अभी हमारे मित्र ने कहा कि बहुत अच्छे ढंग से लोगों को रिलीफ दिया जा रहा है । यह आपको, हमको और सभी को मालूम है कि जब लोग मर जाते हैं, उजड़ते हैं तो उन्हें उन जगहों से ले जाकर शिविरों में रखा जाता है तथा उनके खाने-पीने, कपड़े-लत्ते का प्रबंध सरकार करती ही है । तो क्या यही उसका समाधान है ? हजारों लोगों को अगर जला दिया जाय मैं नहीं चाहता कि बोडोज को जला दिया जाय । आज यह इस देश का दुर्भाग्य है कि हम लोगों के समाज में अगर कोई आदमी आदमी मर जाता है और वह आदिवासी होता है तो हम कहते हैं कि आदिवासी मरा । अगर गैर-आदिवासी मरता है तो हम कहते हैं कि गैर-आदिवासी मरा । अगर हिन्दू मरता है तो कहते हैं कि हिन्दू मरा और अगर मुसलमान मरता है कि कहते हैं कि मुसलमान मरा । अगर बैकवर्ड मरता है तो कहते हैं कि बैकवर्ड मरा और फारवर्ड मरता है तो कहते हैं कि फारवर्ड मरा । मैं कहना चाहता हूं कि इस सदन में, जो कि पूरे देश का सर्वोच्च सदन है इसमें कहना चाहता हूं कि जब तक पूरे देश की जनता को सरकार यह नहीं समझाती है कि न किसी जाति का मरता है और न किसी धर्म का मरता है बल्कि इंसान मरता है और इंसानियत को मारा जाता है । जब तकयह ख्याल आप आप लोगों मन में पैदा नहीं करेंगे, पुलिस और प्रशासन के बीच में पैदा नहीं करेंगे तब तक इंसान और इंसानियत का इस देश में बचना संभव नहीं है । चाहे आप उसकी दुहाई देते रहें, भाषण करते रहे, यह हम करते ही रहते । लेकिन सही मायनों में अगर हम सोचें कि यह इंसानियत की हत्या हुई है, इंसान मारा जाता है, न हिन्दू मारा जाता है न मुसलमान मारा जाता है, न आदिवासी मारा जाता है न हरिजन मारा जाता है वे सब के सब हमारे भाई है ।

इसलिये इस संबंध में हमारे कुछ सुझाव हैं । अगर आप इन घटनाओं को रोकना चाहते हैं तो हमारे पड़ौसी देश जो हैं, चाहे वह बर्मा हो, चाहे बंगला देश हो, चाहे पाकिस्तान हो, इन तमाम देशों के जरिये अमेरिका के इशारों पर इन देशों में जो फंडामेंटलिस्ट ताकतें हैं, ये ताकतें भारत की एकता और अंखडता को तोड़ना चाहती हैं । ये शक्तियां हमारी सीमा पर जो राज्य हैं, उन राज्यों में अलगाववादी आतंकवादी, सांप्रदायिक और जातीय संगठनों की मदद करके पूरे क्षेत्र को, सीमावर्ती इलाकों को तबाह और बरबाद करना चहते हैं । क्या हमारी केन्द्र सरकार को यह मालूम नहीं है । सब मालूम है । आई.एस.आई. की गतिविधियां हों या दूसरी गतिविधियां हों, इन गतिविधियों पर काबू पाने के लिये आपको प्रशासनिक कार्य तो करना ही चाहिये, साथ ही साथ तमाम विपक्षी दलों के साथ मिलकर इन राज्यों में चाहे वह सरकारी दल हों या विपक्षी दल हों, सब को एक आम सहमति बनानी होगी । तभी इस समस्या का समाधान संभव है । ये सांप्रदायवादी और जातिवादी शक्तियां जो हैं ये आज बंगलादेशी घुसपैठियों का नाम लेकर असम में ही नहीं, पश्चिम बगाल और बिहार में भी इस तरह की अफवाहें फैलाकर लोगों को उकसा रही हैं । हम जानते हैं कि बंगला देश के बार्डर के साथ बिहार का बार्डर मिलता है और वहां भी यह सवाल उठाया जा रहा है कि बंगला देश से आकर वे स्थिति को बिगाड़ रहे हैं । आप पहचान कीजिये, घुसपैठियों को आने से आप रोकिये लेकिन सब को घुसपैठियों कह दिया जाय यह तो उचित नहीं है । लेकिन उस इलाके में एक संप्रदाय के लोगों को दूसरे संप्रदाय के लोगों के खिलाफ खड़ा किया जाय तो क्या इससे देश की एकता अक्षुण रहेगी? उस राज्य में सद्भावना कायम रहेगी क्या ? गलती तो रही है । केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार की नीतियां चाहे आदिवासी जनता हो, चाहे बोडो जाति के लोग हों या अन्य आदिवासी जनता हो, उनकी समस्याओं की उपेक्षा राज्य

[श्री जलालुदीन अंसारी]

और केन्द्रीय सरकार करती रही है। हमारे मित्रों ने कहा कि 1977 से लेकर कई साल तक जनता पार्टी का राज रहा है लेकिन सब से अधिक राज इस देश में किस पार्टी का रहा है। उस पार्टी का नाम है कांग्रेस पार्टी चाहे आई हो जाय या ओ हो, यह अलग बात है। लेकिन सब से अधिक दिन तक राज कांग्रेस पार्टी का रहा है। आपकी यह जाबदेही है और हर सरकार की यह जवाबदेही है चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो कि वह जनता की समस्याओं का हल करने के लिये राज-नीतिक दलों को भी विश्वास में ले, उस राज्य की जनता को विश्वास में लिये बिना आप समस्याओं का हल निकाल सकते हैं क्या ? केवल प्रशासनिक कदम नाकाफी है। आदिवासी जनता की जो वाजिब मांगें हैं, हम उनका समर्थन करते हैं। लेकिन किसी को भी इस बात की इजाजत नहीं दी जानी चाहिये कि वह संप्रदायिक दंगा करे, उग्रवाद और आतंकवाद को बढ़ावा दे। इन तमाम बातों को रोकने के लिये सख्त कदम उठाया जाना चाहिये। हम केन्द्र सरकार से मांग करते हैं कि आप उन क्षेत्रों में सही समय पर हस्तक्षेप कीजिये, लगातार आप वहां देखिये, वहां के लोगों को विश्वास में लीजिये ताकि इस प्रकार की घटना दोबारा न दोहराया जाय। वहां जिन लोगों के घर उजड़ गये हैं या जला दिये गये हैं, सामान्य स्थिति पैदा करके, शांति स्थापित करके उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जानी चाहिये। सभी कम्युनिटीज के अदर, सभी जातियों के अन्दर अभियान चलाया जाय, आप सबको साथ लीजिये और पुनः विश्वास पैदा कराया जाये आपसी भाईचारा कायम किया जाये। जो लोग मारे गये हैं। जिनके घर जलाये गये हैं। उनको पुनः बसाया जाना चाहिये। जो मारे गये हैं उनको उचित मुआवजा दिया जाना चाहिये। जो घायल हैं, उनका इलाज होना चाहिये। केन्द्र और राज्य सरकार के बीच समन्वय होना चाहिये। आपस में मिल कर इन समस्याओं को हल करें। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो इस तरह की वारदात फिर दूसमे राज्यों में या उसी राज्य में पुनः हो सकती है। इसलिये इसको फिर से नहीं दोहराया जाय, इसके लिये सरकार को कड़ी चौकसी बरतनी चाहिये और इसके लिये ठोस कदम उठाने चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात यहीं खत्म करता हूं। शुक्रिया।

سمجھ میں آتی ہے۔ مگر ان کی جان کی نگرانی میں
کمی ہو یہ بات سمجھ سے باہر ہے۔ اس لیے جو
لوگ مرے ہیں ہم ان کو بھرپور خراج عقیدت
پیش کرتے ہیں [illegible] حکومت [illegible]
کرتے ہیں کہ مرکزی حکومت وہاں کی آسام
کی حکومت کو برخاست کرے اور وہاں
گئے جو لوگ مرے ہیں ان کے وارثوں کو کم
سے کم دو دو لاکھ روپے فی کس معاوضہ کے
طور پر دیے جائیں اور ان کے گھرانے کے
ایک ایک بچے کو سروس میں لیا جائے تاکہ
ان کے کچھ دکھ درد کو مندمل کیا جا سکے۔ شکریہ۔

گھوٹالوں میں۔ دھو۔ دھو کر جل رہا ہے لیکن دکھ کی بات ہے کہ ان سمسیاؤں کے صحیح سمادھان کے لیے جو ایک راشٹریہ سمجھداری ہونی چاہیے جو ایک دیش بھکتی کا تقاضہ ہونا چاہیے وہ نہ ہو کر کے ہم دلگت بھاوناؤں میں آ کر دلگت راجنیتک لابھ کے لیے ان سمسیاؤں کو صحیح سمے پر حل کرنے کے بجائے اس کو بڑھاوا دیتے ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو گھٹنا ہے اس کی جتنی بھی نندا کی جائے وہ کم ہوگی۔ یہ شرمناک گھٹنا ہے۔ جب ۱۳ جولائی کو ایسے کے علاقوں میں جا رہے تھا کہ سامپردائک تناؤ اور جھگڑے شروع ہو گئے تھے تو وہاں کی سرکار اور کیندریہ سرکار کیا کر رہی تھی۔ ابھی ہمارے منتری نے کہا کہ گرہ منتری پر ابھیوگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں گرہ منتری کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ غلط ہیں۔ اچھے گرہ منتری بہت اچھے ہیں اور اچھے ہونے بھی چاہئیں۔ لیکن ۱۳/ تاریخ کو اس اکشیتر میں جس بات کی شروعات ہوئی اس کو روکنے کے لیے انہوں نے کون سے قدم اٹھائے۔ بسمری کے شرنارتھی کیمپ پر گولی باری کر کے ۶۰-۷۰ لوگوں کو مارا گیا۔ کیا یہ کوئی نئی گھٹنا ہے۔ میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ بھاگلپور دنگے کے وقت ۱۲۵ آدمیوں کو پریوار کے ساتھ ایک اسکول میں لاکر رکھا گیا اور پھر پولیس سنرکشن میں رکھا گیا۔ پولیس کے سنرکشن میں رہے اور پولیس کے سنرکشن میں دنگائیوں نے حملہ کیا۔ پولیس چپ رہی اور ۱۲۵ آدمیوں کا قتل عام ہوا۔ کیا یہ بھارت سرکار کو معلوم ہے۔ جب اس طرح کی گھٹنائیں پچھلے دنوں گھٹت ہو رہی ہیں تو پھر شرنارتھیوں کے کیمپوں پر بھی حملے ہو سکتے تھے۔ اور ہونے اس کے بچاؤ کے لیے پولیس کا سہارا کیوں نہیں لیا گیا۔ ابھی ہمارے منسٹر نے کہا کہ بہت اچھے ڈھنگ سے لوگوں کو ریلیف دیا جا رہا ہے۔ یہ آپ کو ہم کو اور سبھی کو معلوم ہے کہ جب لوگ مر جاتے ہیں، اجڑتے ہیں تو انہیں ان جگہوں سے لے جا کر شیوروں میں رکھا جاتا ہے تتھا ان کے کھانے پینے وغیرہ کا پربندھ سرکار کرتی ہی ہے کیونکہ یہی اس کا سمادھان ہے۔ ہزاروں لوگوں کو اگر جلا دیا جائے۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ بہو ڈوز" کو جلا دیا جائے۔ آج یہ اس دیش کا دربھاگیہ ہے کہ ہم لوگوں کے سماج میں اگر کوئی مر جاتا ہے اور وہ آدی واسی ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ آدی واسی مرا۔ اگر غیر آدی واسی مرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ غیر آدی واسی مرا۔ اگر ہندو مرتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہندو مرا اور اگر مسلمان مرتا ہے تو

کہتے ہیں کہ مسلمان مرا۔ تم بیک ورڈ مرتا ہے تو کہتے ہیں کہ بیک ورڈ مرا اور فارورڈ مرتا ہے تو کہتے ہیں کہ فارورڈ مرا۔ میں کہنا چاہتا ہوں اس سدن میں ہو کر پورے دیش کا سر وچ سدن ہے اس میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک ہم مسلمان کی ہتیا کو ہندو یہ نہیں سمجھیں گے کہ ہندو مرا ہے اور نہ کسی دھرم کا مرا ہے بلکہ انسان مرا ہے اور انسانیت کو مارا جاتا ہے جب تک یہ خیال آپ لوگوں کے من میں پیدا نہیں کریں گے پولیس اور پرشاسن کے بیچ میں پیدا نہیں کریں گے تب تک انسان اور انسانیت کا اس دیش میں بھلا نہیں ہو سکتا ہے چاہے آپ اس کی دہائی دیتے رہیں۔ بھاشن کرتے رہیں۔ یہ ہم کر سکتے ہیں سچے ہیں لیکن صحیح معنوں میں اگر ہم سوچیں کہ یہ انسانیت کی ہتیا ہوئی ہے۔ انسان مارا جاتا ہے نہ ہندو مارا جاتا ہے نہ مسلمان مارا جاتا ہے نہ آدی واسی مارا جاتا ہے نہ ہریجن مارا جاتا ہے وہ سب کے سب ہمارے بھائی ہیں۔

اس لیے اس سمبندھ میں ہمارے کچھ سجھاؤ ہیں۔ اگر آپ ان گھٹناؤں کو روکنا چاہتے ہیں تو ہمارے پڑوسی دیش جو ہیں چاہے وہ برما ہو۔ چاہے بنگلہ دیش ہو چاہے پاکستان ہو۔ ان تمام دشمنوں کے ذریعہ امریکہ کے اشارہ پر ان دیشوں میں جو ہند امنطلسٹ طاقتیں ہیں یہ طاقتیں بھارت کی ایکتا اور اکھنڈتا کو توڑنا چاہتی ہیں۔ یہ شکتیاں ہماری سیما پر جو راجیہ ہیں ان راجیوں میں اتنگ وادی، آتنک وادی، سامپردائک ودھاین سنگٹھنوں کی مدد کر کے پورے دیش کو۔ سیماورتی علاقوں کو تباہ اور برباد کرنا چاہتے ہیں۔ کیا ہماری کیندریہ سرکار کو یہ معلوم نہیں ہے۔ سب معلوم ہے۔ آئی ایس آئی کی گتی ودھیاں ہوں یا دوسری شکتی ودھیاں ہوں۔ ان گتی ودھیوں پر قابو پانے کیلئے آپ کو پرشاسنک کاروائی تو کرنا ہی چاہیے ساتھ ہی ساتھ تمام وپکشی دلوں کے ساتھ مل کر ان راجیوں میں چاہے وہ سرکاری دل ہوں یا وپکشی دل ہوں سب کو ایک عام سہمتی بنانی ہوگی۔ تب ہی اس سمسیا کا سمادھان سمبھو ہے۔ یہ سامپردائک وادی اور جاتی وادی شکتیاں جو ہیں یہ آج بنگلہ دیشی گھس پیٹھیوں کا نام لے کر آسام میں ہی نہیں بلکہ بنگال اور بہار میں بھی اس طرح کی افواہیں پھیلا کر لوگوں کو اکسا رہی ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ بنگلہ دیش کے بارڈر کے ساتھ بہار کا بارڈر ملتا ہے اور وہاں بھی یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ بنگلہ دیش سے اگر وہ استھتی کو بگاڑ رہے ہیں آپ

پہچان کیجیے۔ گھسپیٹھیوں کو آنے سے آپ روکیے لیکن سب کو گھسپیٹھیے کہہ دیا جائے یہ اُچت نہیں ہے۔ لیکن اس علاقہ میں ایک سامپردائے کے لوگوں کو دوسرے سامپردائے کے خلاف کھڑا کیا جائے تو کیا اس سے دیش کی ایکتا اکھنڈ رہے گی۔ اس راجیہ میں سدبھاونا قائم رہے گی کیا۔ غلطی تو رہی ہے۔ کیندریہ سرکار اور راجیہ سرکار کی نیتیاں چاہے آدی واسی جاتی ہو۔ چاہے بوڈو جاتی کے لوگ ہوں یا اننیے آدی واسی جنتا ہو ان کی سمسیاؤں کی اپیکشا راجیہ اور کیندریہ سرکار کرتی رہی ہے۔ ہمارے منتری نے کہا 1967 سے لے کر کئی سال تک جنتا پارٹی کا راج رہا ہے لیکن سب سے ادھیک راج اس دیش میں کس پارٹی کا رہا ہے۔ اس پارٹی کا نام ہے کانگریس پارٹی چاہے آئی ہو جائے یا او ہو جائے۔ یہ الگ بات ہے لیکن سب سے ادھیک دنوں تک راج کانگریس پارٹی کا رہا ہے آپ کی یہ جواب دہی ہے اور ہر سرکار کی یہ جواب دہی ہے چاہے کسی بھی پارٹی کی سرکار ہو کر وہ جنتا کی سمسیاؤں کو حل کرنے کے لیے راجنیتک دلوں کو بھی وشواس میں لے۔ اس راجیہ کی جنتا کو وشواس میں لیے بنا آپ سمسیاؤں کا حل نکال سکتے ہیں کیا۔ کیول پرشاسنک قدم ناکافی ہیں۔ آدی واسی جنتا

کی جو واجب مانگیں ہیں۔ ہم ان کا سمرتھن کرتے ہیں۔ لیکن کسی کو بھی اس بات کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے کہ وہ سامپردائک دنگا کریں اگرواد اور آتنک واد کو بڑھاوا دیں ان تمام باتوں کو روکنے کے لیے سخت قدم اٹھایا جانا چاہیے ہم کیندریہ سرکار سے مانگ کرتے ہیں کہ آپ ان اکشیتروں میں صحیح سمے پر ہستکشیپ کیجیے۔ لگاتار آپ وہاں دیکھیے وہاں کے لوگوں کو وشواس میں لیجیے تاکہ اس پرکار کی گھٹنا کو دوبارہ نہ دوہرایا جائے۔ وہاں جن لوگوں کے گھر اجڑ گئے ہیں یا جلا دیے گئے ہیں سامانیہ استھتی پیدا کر کے شانتی استھاپت کر کے ان کے پنرواس کی ویوستھا کی جانی چاہیے سبھی کمیونٹیز کے اندر سب ہی جاتیوں کے اندر ابھیان چلایا جائے۔ آپ سب کو ساتھ لیجیے اور ان میں وشواس پیدا کیا جائے آپس بھائی چارہ قائم کیا جائے۔ جو لوگ مارے گئے ہیں۔ جن کے گھر جلائے گئے ہیں ان کو پھر سے بسایا جانا چاہیے۔ جو مارے گئے ہیں ان کو اُچت معاوضہ دیا جانا چاہیے۔ جو گھائل ہیں ان کا علاج ہونا چاہیے۔ کیندر اور راجیہ سرکار کے بیچ سمنویہ ہونا چاہیے۔ آپس میں مل کر ان سمسیاؤں کو حل کریں۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو اس طرح کی واردات پھر دوسرے راجیوں میں یا اسی راجیہ میں پھر سے ہو سکتی ہے۔ اس

لیے اس کو پھر سے نہیں دہرایا جائے۔ اس
کے لیے سرکار کو کڑی چوکسی برتنی ہوگی اور
اس کے لیے ٹھوس قدم اٹھانے چاہیئں
ان شبدوں کے ساتھ میں اپنی بات ختم
کرتا ہوں۔ شکریہ۔
(ختم شد)

श्री जनेश्वर मिश्र (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, सुबह हम लोग प्रश्न पहर में डोडा पर बात कर रहे थे और इस समय बोडो पर बात कर रहे हैं। सुबह डोडा, शाम को बोडो, यह इस सदन की नियति बन गई। यह देश का सर्वोच्च सदन है, वहां यह चर्चा और पीड़ादायी चर्चा होती रहे, यह कोई अच्छा लक्षण नहीं है। लेकिन बोडो पर चर्चा क्यों उठाई गई, उसकी इजाजत चेयरमैन साहब ने क्यों दी, हम सदन में बैठे हुये लोग क्यों बहस कर रहे हैं ? केवल इसलिये कि 23 तारीख को 40–50–60 या जो कोई भी नम्बर कहा जा रहा है अखबार से लेकर और यहां तक उतने लोग शरणार्थी शिविर में मार डाले गये हैं। अगर यह लोग मारे नहीं गये होते या दो चार मारे गये होते तब भी क्या हम लोग यह चर्चा करते ? हम को याद आ रहा है, जाफर शरीफ जी इस समय यहां नहीं है, थोड़े दिन के लिये हम रेल विभाग में थे, एक दिन एक दुर्घटना हो गई। अपने विभाग के अधिकारियों से कहा कि हमें जाना है। रेलवे बोर्ड के लोगों ने हम से यह कहा कि आम तौर से 10 के ऊपर लोग मरते हैं तब मिनिस्टर जाता है, 10 से कम होते हैं तो रेलवे बोर्ड के लोग जाते हैं और एक दो मरते हैं तो जनरल मैनेजर चला जाता है। यह अफसरशाही की सोच तो हो सकती है लेकिन लोकशाही भी यही मानती है ? अगर 40–50 लोग नहीं मरे होते तो हमारे उस पूर्वोत्तर इलाके में जो समस्यायें हैं वे समस्यायें क्या नहीं रहतीं, हम उस पर चर्चा करते, नहीं करते ? इस लिये हमने कहा कि यह क्यों चर्चा कर रहे हैं ? इसलिये कि कुछ लोग मर गये हैं, मार डाले गये हैं, शरणार्थी शिविर में मार डाले गये हैं, इसलिये हम गंभीर हो गये हैं। तो यह एक विचित्र किस्म की परिस्थिति बन जाती है। अगर लोक शक्ति, लोक पंचायत समस्याओं के फूटने के बाद ही गौर करेगी और अपना वक्त खराब करेंगे तो इस से समस्या का निदान निकल नहीं सकता है। यह असम में जो समस्या है लगभग सभी आदिवासी इलाकों में इसी तरह की समस्या है। बहुत ही ऊबड़-खाबड़ किस्म के इलाके, नदी, पहाड़ उन में बसे हुये लोग, आजादी मिलने के बाद से, पहले की बात तो थोड़ी देर के लिये छोड़ दिया जाय, आजादी मिलने के बाद से उनके विकास के लिये कुछ भी नहीं हुआ है। उनकी स्वायतत्ता की जो कौंसिल बनती है बीच-बीच में जो मांगे होती हैं या कुछ बातें घटती है उसके कोई मायने नहीं। कहीं-कहीं कोई प्रकृति कुछ ज्यादा हमलावर होती है, उनको आगे नहीं बढ़ने देती। प्रकृति के भी कई रूप होते हैं, कई जगहों पर जैसे कि असम में एक नदी बहती है। उसका नाम ब्रह्मपुत्र है। हिन्दुस्तान की जितनी नदियां हैं या दुनिया की जितनी नदियां हैं उनको हम बेटी कहते हैं, मां कहते हैं, लेकिन असम में जो नदी बहती है उसको "बेटा" कहते हैं, "पुत्र" कहते हैं। तो जो नदी पुत्र बन कर चलती है वह हा-हा कार, बड़ा तूफान, बड़ा बवंडर, सर्वनाश करते हुये चलती है। उसमें जो बसता है वह बर्बाद किस्म का आदमी है। जो कोई भी समाज का संचालन करता है, राज्य चलाता है उसका धर्म होता है कि उस प्रकृति की खराबी का मुकाबला करने के लिये कौन सा इंतजाम करे, कौन सा रास्ता निकाले आदियुग की बात छोड़ दीजिये, गुलामी के जमाने की बात छोड़ दीजिये, सन 47 के बाद से ले करके अब तक उस नदी को बांधने के लिये कोई रास्ता नहीं निकाला है बेटा

नदी है । उसके पेट में पले हुये लोग बसने वाले लोग उनका विकास हो ही नहीं सकता । कुछ मित्रों ने कहा कि आर्थिक समस्या जमीन की समस्या है, लेकिन केवल जमीन की समस्या नहीं है । सन 47 के बाद जिस संस्कृति की बात आप लोग कर रहे थे, जो लोग हिन्दुस्तान के मालिक थे, उन लोगों ने आदिवासियों से कहा था कि तुम अपनी संस्कृति की हिफाजत करना उनकी संस्कृति थी तन कपड़ा पहन करके भौंडे किस्म का नाच खेलना, घटिया किस्म की शराब पीना, हसने के लिये किसी तीज-त्यौहार मेला में संगम के किनारे जाकर स्नान करना नहीं, उसे संस्कृति की हिफाजत इसलिये करनी थी कि हमारी संस्कृति कोई कला है । समाज में बसे हुये लोग, शहरों में बसे हुये लोग पता नहीं कितनी किस्म की कलाओं के दौर से गुजर रहे है । उनको संदेश दिया गया था उस समय उन बड़े लोगों का नाम ले करके मैं यहां विवाद नहीं खड़ा करूगा, कहा गया था कि अपनी संस्कृति की हिफाजत करो । इनके बीच में कोई जाना नहीं चाहिये और तब यह दर्द इधर से उभर रहा है कि हमारे उस इलाके के प्रतिनिधि आये हैं पर वहां के लोग संवादहीन स्थिति में हैं । सन 47 में कहा गया था कि इनमे ज्यादा घुसो मत, इनके बीच में हिलमल कर न रहो, इनकी सांस्कृतिक हिफाजत होनी चाहिये । कुछ संस्कृति के, कला के शौकीन लोग, हिन्दुस्तान के मालिक बने थे उन दिनों और उनको इस बात का शौक हो गया था कि उनकी संस्कृति, उनकी कला कभी-कभी 26 जनवरी को यहां झांकी के तौर पर इंडिया गेट के आस-पास मंडराती हुई दिखाई पड़े । उनका विकास नहीं हो पाया, उनकी संस्कृति का विकास नहीं हुआ सामाजिक तौर पर वे शोषण के शिकार रहे, आर्थिक तौर पर वे शोषण के शिकार रहे । जिस प्राकृति की गोद में पलते हैं उसकी लकड़ी, उसके जानवर, उसकी खाल पर उनकी जिन्दगी पला करती थी । उससे निकले हुये फल का शराब बना करके वे अपना गम गलत किया करते थे । वह लकड़ी, वह जानवर, उनके मारने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया । तो उनकी जिन्दगी का शोषण बहुत हुआ है और ऐसा नहीं है कि एक जगह हुआ है, यह सब जगह हुआ । हमारे नैनीताल के पहाड़ी इलाके में जो आदिवासी बसे रहते हैं वे अपना दर्द कहते हैं ? बस्तर के इलाके में जो आदिवासी बसे रहते हैं वे अपना दर्द कहते हैं । अलग-अलग किस्म के दर्द ये ऊबड़-खाबड़ किस्म की जमीन पर रहने वाले लोग, प्रकृति ने जिनके संरक्षण के लिये कोई इंतजाम नहीं किया, उसका दोहन करने के लिये मैदान के लोग यहां से चले गये । इसमें आरोप यह मत लगाइये कि केवल बांगला देश से लोग भाग कर आ रहे हैं । बांगला देश के लोगों को मैं अपना दुश्मन नहीं मानता । आज से थोड़े दिन पहले वह हमारे भाई थे । हम एक घर के थे । हम कभी नहीं मानते कि वह हमारे दुश्मन हैं । आज कुछ लोगों की जेहनियत ऐसी बन गई है तो उन लोगों को मैं यह कहना चाहता हूं कि इस तरह बोडो, गैर बोडो के नाम पर, मुस्लिम के नाम पर, शरणार्थी और घुसपैठिये के नाम पर, बांगला देशी और हिन्दुस्तानी के नाम पर पूरी तरह से देश की एक तस्वीर को हम घिनौनी किस्म की बना रहे हैं, जो कि अच्छा नहीं है । इससे देश टूट जायेगा ।

महोदय, 40 साल, 45 साल से जो लोग लगातार प्रकृति की गोद में उपेक्षा के शिकार रहे हैं वह धीरे धीरे उठ रहे हैं । कभी-कभी स्वायतत्ता की मांग करते हैं तब उनके लिये कोई कौंसिल बनाकर झुनझुना की तरह से थमा दिया जाता है उनके द्वारा, जो दिल्ली की कुर्सी पर बैठे होते हैं । इसमें मैं यह बात नहीं करता कि वह कांग्रेस पार्टी के होते हैं या जनता पार्टी के होते हैं या जनता दल के होते हैं । इस बहस में मैं नहीं जाता, लेकिन उनको झुनझुना थमा दिया जाता है । इससे भी उनको सतोष नहीं होता । कई इलाके हमारे उत्तर प्रदेश प्रदेश के ऐसे हैं, जहां पर लोगों ने कहा था कि हमको उत्तरांचल या उत्तराखंड दे दो और उस समय की सरकार के लोगों ने कहा था कि तुमको हम स्वायत्ता की एक समिति दे रहे हैं । इस पर उन सबने कहा था कि नहीं लेंगे ।

ऐसे ही असम के इलाके में भी होता है कि अपना इंतजाम खुद करो, खुद मुख्तियारी का हक ले लो, करो इंतजाम। कहां से करेंगे? उनके पास साधन ही नहीं हैं और अभाव में जो कुछ भी इंतजाम करने के लिये पैसा दिया जायेगा, चाहे केन्द्र से दिया जायेगा या राज्य से दिया जायेगा, वह भ्रष्टाचार का माध्यम बनेगा क्योंकि अभावग्रस्त मानसिकता विकास नहीं किया करती, वह भ्रष्टाचार फैलाया करती है। तो वह लोग अभावग्रस्त हालत में हैं और खतरा इस बात का हो गया है कि यह देश टूट जायेगा।

महोदय, वहां जिस तरह से लोग मर रहे हैं, उसके लिये यह मत समझिये कि यह केवल असम की घटना है। वहां जो 40 लोग मर गये, 50 लोग मर गये, 60 लोग मर गये या 200 लोग घायल हो गये तो इसका असर इलाहाबाद के लोगों पर भी पड़ा है, इसका असर पटना के लोगों पर भी पड़ा है और उनके दिल में दहशत भी पैदा हुई और गुस्सा भी पैदा हुआ क्योंकि वह भी हमारे भाई हैं, जो एक जगह तम्बू में लेटे हुये हैं और मार डाले गये। उनके लिये दर्द लोगों को हुआ है, गुस्सा पैदा हुआ है। अगर उसी समय हम संदेश देने लगे तो ठीक नहीं। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है गृह राज्य मंत्री जी के बारे में, उनका बयान मैंने अखबार में पढ़ा था कि बांगला देश की सरहद सील कर दी गई है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : भूटान की।

श्री जनेश्वर मिश्र : ऐसा लगता है, मानो बांगला देश के लोग आये थे, जो सरहद सील की जा रही है। पलटन भेज दी गई है उन सबका मुकाबला करने के लिये, राज्य सरकार की मदद के लिये पैरा-मिलिटरि भेज दी गई है। यह बयान पढ़ने के बाद मैंने माथा ठोक लिया कि मिलिटरी से या किसी सरहद को सील करके क्या इस समस्या का हल किया जा सकता है? यह तो वहां के बदले हुये लोगों का दर्द है, जो उभर रहे हैं।

महोदय, हमको अच्छी तरह से याद है जनता दल के जमाने में मैं गुवाहाटी गया था। वहां एक डाक बंगला में रूका था। वहां पता लगा कि पान बाजार मोहल्ले में, जहां मारवाड़ी और बिहारी लोग बहुत रहते हैं, एक कोई सेठ मार डाला गया है। तो मैं टहलता पान बाजार चला गया। एक दुकान पर खड़े होकर पान खाने लगा। बिल्कुल सामान्य स्थिति थी। थोड़ी सी दुकानदार लोगों में हलचल थी। तो हमने पूछा कि कि क्यों मारा गया? किसी ने बताया कि यह सब बाहर से आकर के धनी हो गये, लूट ले गये और हम असम के लोगों को कुछ नहीं मिला, हम बर्बाद हो गये। तो उस जमीन पर पैदा होने वाले के मन में एक दर्द होता है, जब कोई कलकत्ता से आकर या पटना से आकर या लखनऊ से आकर वहां मालामाल हो जाता है, करोड़पति हो जाता है, करोड़पति बन जाता है। ऐसा बंगाल में भी होता है। बंगाल के हमारे मित्र माफ करेंगे यह कहने के लिये। जब बड़ा बाजार में देखते हैं बड़ी बड़ी कोठी और खुद वह किसी दफ्तर में बाबूगिरी करते हैं तो उनके दिल में दर्द होता है कि हमारी जमीन को लूटकर यह धनी हो गया। ऐसा बम्बई में भी होता है। तो यह दर्द स्वाभाविक है। जो लोग तिकड़म जानते हैं, रुपया कमाने के लिये चले जाते हैं गरीब इलाके में और वहां रुपया कमा लेते हैं, मगर वहां का आदमी भूखा का भूखा रह जाता है तो उसके दिल में दर्द होता है। यही आज समाज में हालत है कि बाजार का आदमी, शहर का आदमी, गांव का आदमी जब आदिवासियों के बीच में जाता है तो उनकी मेहनत मशक्कत की कमाई खा लेता है और उससे कहता है कि तुम अपनी संस्कृति की रखवाली के लिये समाज में मत जाओ। उसको अलग कर देना चाहता है। तो यह दर्द है उन लोगों का और इस दर्द को समझने के लिये, मैं नहीं जानता, गृह मंत्रालय काबिल होगा या नहीं? वह ऐसा कर पायेगा या नहीं? इस पर संपूर्ण भारत सरकार को देखना होगा। इसमें मानव संसाधन मंत्री को भी लेना चाहिये, कोई संस्कृति विभाग का मंत्री हो तो उसको भी लेना चाहिये। इस पर संपूर्ण पूरे तौर पर सोचना होगा और

क्योंकि यह दर्द जो है कहीं न कहीं, कभी न कभी उभरता ही रहेगा । शास्त्री जी, यह मत कहिये कि उड़ीसा का गरीब आदमी नहीं उभर रहा है । वह भी किसी न किसी दिन उभर जायेगा । वह भी उभरेगा । गरीब को उभरना आता है । गरीबी कितने दिनों तक वह झेलेगा? कोई उसका कुछ कहा नहीं जा सकता ।

अगर इस सारे सवाल पर आप बहस करेंगे कि पंजाब में उग्रवाद कैसे आ गया, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह बहस मत उठाइए । पंजाब की जितनी दुर्दशा आजादी मिलने के बाद से की गई है, किसी भी सूबे की उतनी दुर्दशा की गई है क्या ? सन् 1947 में पंजाब बांटा गया था दिल्ली में बैठकर और सन् 1947 के बाद पंजाब 3 टुकड़ों में किया गया दिल्ली में बैठकर । हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार को जब बांटने की बात चलती है, झारखंड मुक्ति मोर्चा वाले यह मांग करते हैं या उत्तराखंड वाले यह मांग करते हैं तो दिल्ली मौन रह जाती है । हाईकोर्ट को बांटने की बात जब चलती है तो लोग मुंह लटका लेते हैं कि इतना बड़ा सूबा कैसे बंटेगा, देश टूट जाएगा ।

एक सूबे को आपने बार-बार बांटा पता नहीं उनके कितने गुरुद्वारे, कितने मकबरे दूसरे हिस्सों में चले गए, उनकी रिश्तेदारियां छूट गई, वे अपने देश से उजाड़कर बाहर फेंक दिए गए । उनके मन में गुस्सा नहीं आया, फिर भी वे किसी तरह से जीना चाहते थे । तो आप उनके गुरुद्वारों पर कब्जा करने लगे । बीच में थोड़े दिनों के लिए दूसरे लोगों की सरकार आ गई तो आपने भिंडरावाले को आगे चढ़ा दिया और वह बाद में एक सिरदर्द बन गया । अगर में वह सारा इतिहास सुनाऊंगा तो आपको मालूम पड़ेगा कि उनका दर्द कोई नाजायज किस्म का दर्द नहीं है । उनको समझाने की कोशिश करनी पड़ेगी आपको ।

महोदय, कई बार इस तरह के सवाल उठे हैं । फखरूद्दीन साहब जब दिल्ली सरकार के मंत्री थे, तब मैं नया-नया एम. पी. होकर आया था । तब भी यह सवाल उठा था कि वह बंगला देश से मुसलमानों को बुलाकर असम में बसा रहे हैं । बिहारी मुसलमानों को बुलाने के खिलाफ आंदोलन चला था । यह मुसलमानों के खिलाफ आंदोलन क्यों ? बोडो या गैर-बोडो के खिलाफ किसी की कोई सोच हो सकती है, अक्लियत के खिलाफ, असलियत के खिलाफ हो सकता है कि किसी की कोई सोच हो लेकिन संपूर्ण सोच वह नहीं है । अभी हमारे एक दोस्त ने मंदिर-मस्जिद का सवाल उठा दिया था । अयोध्या में राम पैदा हुए थे लेकिन राम इस देश को जोड़ने वाले नेता थे उत्तर से दक्षिण तक लेकर । कई लोग मथुरा का सवाल उठाते हैं । मथुरा में कृष्ण मेले होंगे लेकिन कृष्ण असम से लेकर पश्चिम तक हिंदुस्तान को जोड़ने वाले देवता थे । उनको अयोध्या में और मथुरा में समेट देंगे तो हो सकता है कि उनकी राजनीति कुछ देर के लिए चल जाए लेकिन हिंदुस्तान टूट जाएगा । एक जगह की चीज नहीं थे वे एक उत्तर से दक्षिण को जोड़ता था तो दूसरा पूरब से पश्चिम को जोड़ता था । अगर आप केवल यह मानकर चलेंगे कि इस देश को अंग्रेज जोड़कर चले गए, मुसलमान जोड़कर चले गए या आजादी मिलने के बाद इतना बड़ा देश बना, तो मैं इससे सहमत नहीं हूं । कई तरह के मजहब, कई तरह की संस्कृतियां इस देश को जोड़ती रही हैं और आज इस बात का खतरा पैदा हो गया है कि ये संस्कृतियां टूट रही हैं, लड़खड़ा रही हैं ।

एक बार जब 40–50 आदमी कत्ल हो जाते हैं किसी शरणार्थी शिविर में तो उसका प्रभाव सारे देश की मानसिकता पर पड़ता है, केवल असम पर नहीं पड़ता । बार-बार विपक्ष के लोग मांग करते हैं कि वहां के मुख्य मंत्री को हटा देना चाहिए तो उसका मतलब यह नहीं होता है कि वहां के मुख्य मंत्री से उनकी कोई दुश्मनी है ...(व्यवधान)

श्री नारायण प्रसाद गुप्ता (मध्य प्रदेश) आप एकता की बात कर रहे हैं, बताइए महाभारत क्यों हुआ ?

उपसभाध्यक्ष (श्री सतीश अग्रवाल) : माननीय सदस्य कृपया हस्तक्षेप न करें। मिश्र जी, अब आप समाप्त कीजिए।

श्री जनेश्वर मिश्र : महोदय, दो सुझाव मैं देना चाहता हूं। कल इनकी पार्टी के माथुर साहब बोल रहे थे तो उनसे मैंने कहा था कि क्यों नहीं महासंघ की बात उठाते हैं। जरूरी हो गया है कि सरहद पर यह तनाव खत्म हो क्योंकि वहां हमारे पिछड़े इलाके हैं, आदिवासी इलाके हैं। मैं भाजपा के मित्रों से कहूंगा कि किसी जमाने में इन्होंने "अखंड भारत" का नारा दिया था। हमने अपने साथियों से कहा था कि आप भी "महासंघ" का नारा दे रहे हो। भाजपा में और हममें यह फर्क है कि हम हिंदुस्तान में जो अकलियत के लोग हैं, उनको गले लगाकर जो दूसरे देशों में अकसरियत के लोग हैं, उनको संदेश देना चाहते हैं कि हम एक होना चाहते हैं यार-मोहब्बत के साथ। और यहां जो अकलियत के लोग हैं उनको घृणा देकर के, नफरत देकर के अखंड भारत की बात करना चाहते हैं। ... (व्यवधान)

5.00 P.M.

श्री नारायण प्रसाद गुप्ता : पंडित जी, आप अखंडता की बात करते हैं। ... (व्यवधान) आप तो अपनी पार्टी रोज तोड़ते हैं। .... (व्यवधान)

श्री जनेश्वर मिश्र : वहां 40 आदमी मरे हैं। हम मांग करते हैं कि वहां के मुख्य मंत्री इस्तीफा दें। भारत सरकार को दबाव डालना चाहिए ताकि सारे हिन्दुस्तान का आदमी समझ सके कि इंसानियत की जिंदगी खतरे में एक शरणार्थी शिविर में पड़ी हुई होने के कारण वहां सर्वोच्च सत्ता में बैठे हुए व्यक्ति ने इस्तीफा दिया, तो लोगों को इतमिनान मिलेगा। इसके अलावा यह सीमाएं सील करने से समस्याएं हल नहीं होंगी। भारत, पाकिस्तान और बगला देश की सीमाओं को खोलने से ही इस समस्याओं का हल हो सकता है। नफरत और शक के आधार पर किसी कौम की हिफाजत लम्बे अरसे तक नहीं की जा सकती।

उपसभाध्यक्ष (श्री सतीश अग्रवाल) : माननीय सदस्यों को मैं सूचित करना चाहूंगा कि श्री बलराम जाखड़ जी फ्लड सिचुएशन के बारे में एक स्टेटमेंट दे रहे हैं। वह उसको ले करेंगे। उसके बारे में प्रश्न पूछने की अनुमति कल यहां दी जाएगी। यह कंसेंसस है हाउस का।

STATEMENT BY MINISTER

Flood situation in the country

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI BALRAM JAKHAR): Sir, with your permission, I lay a statement regarding the flood situation in the country, on the Table of the House.

Sir, I seek leave of the House to make a statement on the current flood situation in the country and the relief and rehabilitation measures taken by the Government.

South West monsoon, 1994 arrived in Kerala on 28th May, 1994, three days in advance and covered the entire country by 30th June, 1994 about 15 days in advance to the normal time of coverage. During the period from June 1 to July 20, the cumulative rainfall has been excess in 18 of tht 35 meterological sub-divisions into which the country is divided. Out of 415 districts, 174 districts received excess rainfall wrile 112 received normal rainfall. The rainfall has remained deficient in the North-Eastern States West Bengal, Sikkim, Bihar Plains, Hills of West Uttar Pradesh and Marathwada. Substantially heavy rainfall ranging upto 114 per cent has been received in Orissa, Bihar Plateau, Harvana, Himachal Pradesh, Rajasthan, Madhya Pradesh, Gujarat, Maharashtra, Karnataka and Jammu and Kashmir.

An unusual feature of the rainfall this year has been that the traditionally low rainfall areas have received good rains like in Saurashtra Kutch, West Rajasthan and North Interior Karnataka. On the other hand, the